जून 2024 ■ वर्ष : 33 ■ अंक : 10 ₹135

सिविल सर्विसेज़

क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

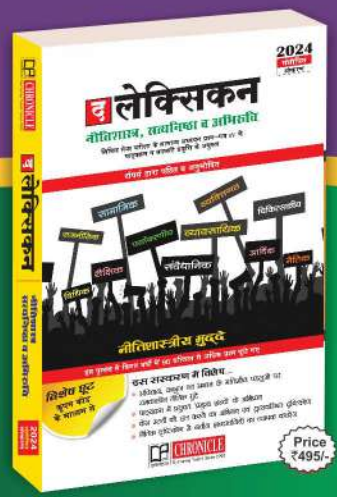

IAS/PCS प्रारंभिकी 2024

भारतीय अर्थव्यवस्था

प्रमुख संकेतक

जीएस मॉक टेस्ट

सेट 1 एवं 2 : व्याख्या सहित हल

हल प्रश्न-पत्र

JPSC - संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2023

विशेष आलेख

- भारत के अनौपचारिक क्षेत्र का औपचारीकरण : आर्थिक गतिविधियों के औपचारीकरण हेतु नीतिगत उपायों की आवश्यकता
- पश्चिम एशिया संकट : भारत एवं विश्व के लिए निहितार्थ
- जलवायु प्रत्यास्थ कृषि : धारणीयता एवं खाद्य सुरक्षा हेतु आवश्यक
- जलवायु परिवर्तन तथा नागरिक अधिकार : गुणवत्तापूर्ण जीवन हेतु स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यकता
- सितवे एवं चाबहार बंदरगाह : पड़ोसी देशों में भारत की बंदरगाह विकास परियोजनाओं के रणनीतिक निहितार्थ
- भारत में खाद्य सुरक्षा : विनियमन एवं चुनौतियां

अन्य आकर्षण

न्यूज बुलेट्स
पत्रिका सार : अप्रैल 2024 में प्रकाशित पत्रिकाओं पर आधारित
चर्चित शब्दावली
संसद प्रश्नोत्तरी
फैक्ट शीट : लॉजिस्टिक्स एवं फार्मा क्षेत्र
समसामयिक प्रश्न
वनलाइनर करेंट अफेयर्स

जून 2024 सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल 1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

www.chronicleindia.in

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

facebook/civilserviceschronicle

जून 2024
❑ वर्ष 33 ❑ अंक 10

इस अंक में

99 भारतीय अर्थव्यवस्था

प्रमुख संकेतक

इस विशेष खंड में, हम भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख आर्थिक संकेतकों से संबंधित सार्थक एवं परीक्षोपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं। इन संकेतकों से संबंधित यह संक्षिप्त और प्रासंगिक जानकारी आपको आगामी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में सहायता करेगी।

57 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024

जीएस मॉक टेस्ट

सेट-1 एवं 2

ये प्रश्न सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की अद्यतन प्रकृति और बदलते पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं; इन प्रश्नों की व्याख्या में हमने प्रश्न में पूछे गए सभी आयामों को कवर किया है।

सामयिक आलेख

06 भारत के अनौपचारिक क्षेत्र का औपचारीकरण : आर्थिक गतिविधियों के औपचारीकरण हेतु नीतिगत उपायों की आवश्यकता
09 जलवायु प्रत्यास्थ कृषि : धारणीयता एवं खाद्य सुरक्षा हेतु आवश्यक
11 पश्चिमी एशिया संकट : भारत एवं विश्व पर प्रभाव

इन फोकस

14 जलवायु परिवर्तन तथा नागरिक अधिकार : गुणवत्तापूर्ण जीवन हेतु स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यकता
15 सितवे एवं चाबहार बंदरगाह : पड़ोसी देशों में भारत की बंदरगाह विकास परियोजनाओं के रणनीतिक निहितार्थ
17 भारत में खाद्य सुरक्षा : विनियमन एवं चुनौतियां

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय परिदृश्य

न्यायपालिका 18
शासन प्रणाली 19
राष्ट्रीय मुद्दे 21
संविधान एवं राजव्यवस्था 22
केंद्र-राज्य संबंध 22
समिति एवं आयोग 23
बैठक एवं सम्मेलन 23

सार्वजनिक नीति

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 24
जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निवारक निरोध 25
अंग प्रत्यारोपण निरीक्षण पर राज्यों को दिशा-निर्देश 25

रिपोर्ट एवं सूचकांक

राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक 26
अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक 26

सामाजिक परिदृश्य

स्वास्थ्य 29
अतिसंवेदनशील वर्ग 29
सामाजिक कल्याण 30
महिला सशक्तीकरण 31

कल्याणकारी योजनाएं

सीडीपी-सुरक्षा प्लेटफॉर्म 32
ईशान पहल 32

विरासत एवं संस्कृति

व्यक्तित्व 33
विरासत स्थल एवं स्मारक 34
उत्सव एवं पर्व 35
पुरातात्विक साक्ष्य 35

आर्थिक परिदृश्य

मुद्रा एवं बैंकिंग 36
करारोपण 37
वित्त क्षेत्र 37
व्यापार एवं निवेश 39
अवसंरचना 39

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन

संधि एवं समझौते 40
वैश्विक पहलें 41
बैठक एवं सम्मेलन 42
संगठन एवं फोरम 43
भारत के पड़ोसी देश 43
विदेश नीति 44
अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम 45
मानचित्र के माध्यम से 46

पर्यावरण एवं जैव विविधता

जलवायु परिवर्तन 47
पर्यावरण संरक्षण 49
ऊर्जा एवं सतत विकास 50
पर्यावरणीय अवनयन व प्रदूषण 51
आपदा प्रबंधन 51

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान 52
स्वास्थ्य विज्ञान 54
नवीन प्रौद्योगिकी 54
रक्षा विज्ञान 55
जैव-प्रौद्योगिकी 56

प्रतियोगिता क्रॉनिकल

राज्य परिदृश्य

उत्तर प्रदेश, बिहार 116
मध्य प्रदेश 116
गुजरात 116
महाराष्ट्र, ओडिशा 117
त्रिपुरा, केरल 117
कर्नाटक, अंडमान एवं निकोबार 117

न्यूज बुलेट्स 118-130

लघु सूचिका

चर्चित व्यक्ति/नियुक्ति 131
निधन, ... 131
पुरस्कार एवं सम्मान 132

खेल परिदृश्य

खेल व्यक्तित्व 133
टेनिस, तीरंदाजी, खेल पुरस्कार 133

परीक्षा सार 134-146

झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रा. परीक्षा-2023 (व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र)

पत्रिका सार : योजना, कुरुक्षेत्र एवं साइंस रिपोर्टर 147-155

चर्चित शब्दावली 156

संसद प्रश्नोत्तरी 157

फैक्ट शीट 158

समसामयिक प्रश्न 159-160

वनलाइनर करेंट अफेयर्स 161-162

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं इम्प्रेशन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नंबर C-18-19-20-21, सेक्टर-59, नोएडा-201301 से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

भारत के अनौपचारिक क्षेत्र का औपचारीकरण

आर्थिक गतिविधियों के औपचारीकरण हेतु नीतिगत उपायों की आवश्यकता

• डॉ. अमरजीत भार्गव

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था उन उद्यमों का प्रतिनिधित्व करती है जो पंजीकृत नहीं हैं, तथा जहां नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य लाभ प्रदान नहीं किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था में औपचारिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनुपालन बोझ को कम करने, प्रोत्साहन प्रदान करने, कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा एक सक्षम व्यावसायिक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, औपचारिक अर्थव्यवस्था के लाभों के संदर्भ हितधारकों को जागरूक बनाने के साथ आर्थिक गतिविधियों में रूपांतरण हेतु संस्थागत कारकों का विनियमन भी महत्वपूर्ण है।

हाल ही में मानव विकास संस्थान (IHD) तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी 'भारत रोजगार रिपोर्ट 2024' के अनुसार भारत में 81.1% कार्यरत व्यक्ति अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2022 में भारत के समग्र रोजगार परिदृश्य में 'स्व-रोजगार' (55.8%) प्राथमिक स्रोत बना हुआ है; इसके पश्चात 'आकस्मिक' और 'नियमित' रोजगार की स्थिति क्रमशः 22.7% और 21.5% दर्ज की गई है।

* सरकारी नियंत्रण से बाहर उत्पादन की छोटी और बिखरी इकाइयां अनौपचारिक क्षेत्र की सामान्य विशेषता मानी जाती हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में मजदूरी दर, कार्य के घंटे तथा रोजगार से संबंधित अन्य नियमों/कानून का स्पष्ट पालन नहीं किया जाता है।
* आर्थिक गतिविधियों तथा रोजगार की अनौपचारिक स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। इसके विनियमन के अभाव में एक तरफ जहां देश में आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या की एक बड़ी संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है; तो वहीं दूसरी तरफ, आंकड़ों के अभाव में सरकार इस क्षेत्र के लोगों के लिए उचित नीतियों का निर्माण करने में अक्षम है।
* इस संदर्भ में, भारत के अनौपचारिक क्षेत्र की व्यापकता एवं इसको औपचारिक बनाने के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

भारत के अनौपचारिक क्षेत्र की स्थिति

* **परिभाषा:** 'आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन' (OECD) के अनुसार किसी भी देश के कार्यबल का वह भाग जो राष्ट्रीय श्रम कानून, आय कर, सामाजिक सुरक्षा तथा वेतन भुगतान एवं अवकाश जैसे रोजगार लाभों के अधीन नहीं है, को अनौपचारिक क्षेत्र में रखा जाता है।
* **शामिल गतिविधियां:** स्ट्रीट वेंडिंग, कारीगर, घरेलू व्यवसाय, स्थानीय परिवहन कर्मचारी, दुकान कर्मचारी, घरेलू नौकर, सफाई एवं कचरा संग्रहण जैसी सामुदायिक सेवाओं में संलग्न कर्मचारी तथा जूता निर्माण, परिधान एवं कढ़ाई आदि संबंधी कार्य।
  - अनौपचारिक रोजगार में लिखित अनुबंध, नियमित भुगतान, निश्चित अवकाश जैसी सुविधाओं का अभाव होता है। इस क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक न्यूनतम वेतन, अपर्याप्त भुगतान तथा दुर्गम परिस्थितियों में कार्य करने के लिए विवश रहते हैं।
* **अनौपचारिक क्षेत्र का आकार:** 'भारत रोजगार रिपोर्ट' के अनुसार देश की जीडीपी (GDP) के कुल आकार में लगभग आधा योगदान अनौपचारिक क्षेत्र का है।
  - भारत के अनौपचारिक श्रमिकों की संख्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोग कृषि तथा अन्य संबंधित गतिविधियों में संलग्न हैं।
* इसी प्रकार, 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट' (PLFS) 2022-23 के अनुसार, 74% गैर-कृषि श्रमिक 'स्वामित्व और साझेदारी' (Ownership and Partnership) क्षेत्र से संबंधित हैं, ऐसे क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
* **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) में वृद्धि:** PLFS के अनुसार, 2017-18 और 2022-23 के बीच, सभी उम्र (ग्रामीण+शहरी) के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) 34.7% से बढ़कर 41.1% हो गया है। इससे संकेत मिलता है कि, भारत में जनसंख्या वृद्धि के साथ अनौपचारिक उद्यमों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।
* **आय एवं मजदूरी:** ई-श्रम पोर्टल पर नामांकित अनौपचारिक क्षेत्र के 94% से अधिक श्रमिक प्रति माह 10,000 रुपये से कम अर्जित करते हैं।
  - इस पोर्टल पर नामांकित लगभग 52.11% श्रमिक कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। इसके पश्चात घरेलू कर्मचारियों तथा निर्माण श्रमिकों का स्थान है।

अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण की आवश्यकता क्यों है?

* **कर आधार का विस्तार:** अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने से अधिक व्यवसाय और व्यक्ति कर के दायरे में आएंगे, इससे कर आधार का विस्तार करने में मदद मिलेगी। कर आधार में विस्तार होने से सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होगी, इस अतिरिक्त प्राप्त आय का उपयोग सार्वजनिक कल्याण और विकास कार्यक्रमों के लिए किया जा सकेगा।

जलवायु प्रत्यास्थ कृषि

धारणीयता एवं खाद्य सुरक्षा हेतु आवश्यक

• संपादकीय डेस्क

वैश्विक स्तर पर जलवायवीय अनिश्चितता संपूर्ण मानव समुदाय के समक्ष विभिन्न चुनौतियां उत्पन्न कर रही है। ऐसे में सर्वाधिक विकराल समस्या जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली खाद्य असुरक्षा की है। परिवर्तनशील जलवायु को देखते हुए अब कृषि क्षेत्र में भी परिवर्तन वर्तमान समय की मांग है। ऐसे में 'जलवायु प्रत्यास्थ कृषि' (Climate Resilient Agriculture) जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले खाद्य असुरक्षा के संकट का एक समाधान हो सकती है।

24 अप्रैल, 2024 को जारी खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट (GRFC) के अनुसार वर्ष 2023 में 59 देशों में लगभग 282 मिलियन लोगों को उच्च स्तर की तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। इस रिपोर्ट के अनुसार चरम मौसमी घटनाएं खाद्य संकट के लिए जिम्मेदार दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक थीं।

अवधारणा

* जलवायु प्रत्यास्थ कृषि एक दृष्टिकोण है, जिसमें जलवायु परिवर्तनशीलता के तहत दीर्घकालिक उच्च उत्पादकता और कृषि आय प्राप्त करने के लिए फसल एवं पशुधन उत्पादन प्रणालियों के माध्यम से मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों का संवहनीय रूप से उपयोग करना शामिल होता है।
* जलवायु प्रत्यास्थ कृषि को यदि हम सामान्य अर्थ में समझें, तो इसे जलवायु अनुकूल कृषि के रूप में समझा जा सकता है; अर्थात ऐसी कृषि जो परिवर्तनशील जलवायु के अनुसार स्वयं को अनुकुलित कर सके।

आवश्यकता

* विश्व के कई देश आपदाओं और संघर्षों के कारण खाद्य संकटों का सामना कर रहे हैं; हालांकि खाद्य सुरक्षा, अपर्याप्त खाद्य भंडार, बुनियादी खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव, कृषि-ईंधन की उच्च मांग और अचानक मौसम परिवर्तन से भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। ऐसे में जलवायु प्रत्यास्थ कृषि खाद्य असुरक्षा से निपटने हेतु महत्वपूर्ण है।
* जलवायु परिवर्तन की स्थिति में जलवायु प्रत्यास्थ कृषि, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भूख एवं निर्धनता को कम कर सकती है। साथ ही उत्पादन को संवहनीय तरीके से बनाए रख सकती है।
* भारत की लगभग 58% जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर है तथा अन्य कृषि आधारित उद्यम भी देश के आर्थिक विकास हेतु महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में जलवायु प्रत्यास्थ कृषि आवश्यक है।
* तापमान बढ़ने से फसल की उत्पादकता पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। उच्च तापमान फसल की अवधि को कम कर सकता है। इसलिए ऐसी फसल प्रणाली की आवश्यकता है, जो जलवायु प्रत्यास्थ हो।

भारतीय परिदृश्य

* भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, फसल की पैदावार जलवायु के प्रति संवेदनशील बनी हुई है तथा तापमान और वर्षा पैटर्न में उतार-चढ़ाव फसलों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिससे भारत में खाद्य सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है।
* 1901 से 2018 के बीच भारत का औसत तापमान लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। हाल की 30-वर्ष की अवधि (1986-2015) में, वर्ष के सबसे गर्म दिन और सबसे ठंडी रात के तापमान में क्रमशः 0-63°C और 0-4°C की वृद्धि हुई है।
* तापमान में वृद्धि, वर्षा परिवर्तनशीलता और सिंचाई हेतु उपलब्ध जल में कमी के कारण 2100 तक अधिकांश फसलों की उत्पादकता 10-40% घटने की संभावना है।
* जलवायु परिवर्तन का प्रमुख प्रभाव वर्षा आधारित या असिंचित फसलों पर पड़ेगा, जिनकी खेती लगभग 60% फसल भूमि में की जाती है। सर्दियों के तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से भारत में वर्षा आधारित गेहूं की उपज में 0.45 टन प्रति हेक्टेयर की कमी आने का अनुमान है।

जलवायु प्रत्यास्थ कृषि के अनुकूल रणनीतियां

* **सहनशील फसलें (Tolerant Crops):** सूखे की समस्या के समाधान के लिए सूखा सहिष्णु बीजों की आवश्यकता है, जैसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में चयनित किसानों तक चना और अरहर की बी.डी.एन 708 (BDN 709) नामक सूखा सहिष्णु किस्मों की पहुंच सुनिश्चित की गई है।
* **मृदा में सुधार:** उचित पोषक तत्व प्रबंधन द्वारा मृदा स्वास्थ्य में सुधार जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि प्रत्यास्थता की एक प्रमुख रणनीति है। मृदा कार्बन का निर्माण, मृदा कटाव को कम करना और मृदा जल धारण क्षमता में सुधार के द्वारा कृषि प्रत्यास्थता को बढ़ाया जा सकता है।
* **जल प्रबंधन:** वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चक्रण द्वारा भू-जल स्तर में सुधार किया जा सकता है। तालाबों एवं चेक डैमों द्वारा खेत के स्तर पर जल भण्डारण एवं जल उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही सिंचाई में टपकन विधि तथा शून्य जुताई (Dripping Method and Zero Tillage) का उपयोग भी किया जा सकता है।
* **एकीकृत कृषि (Integrated Agriculture):** इसके अंतर्गत पशु अवशेषों एवं फसल अवशेषों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है; जैसे गोबर का उपयोग उर्वरक के रूप में, बायोगैस का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए तथा फसल अवशेषों का प्रयोग पशु चारे के रूप में करना आदि।

जलवायु प्रत्यास्थ कृषि के समक्ष चुनौतियां

* बदलती जलवायु ने कृषि के सम्मुख अनेक चुनौतियां पेश की हैं। इसका सामना करने के लिए जलवायु प्रत्यास्थ कृषि पद्धति को अपनाया जा रहा है, किन्तु इसके समक्ष भी कई चुनौतियां भी विद्यमान हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

पश्चिमी एशिया संकट

भारत एवं विश्व पर प्रभाव

• संपादकीय डेस्क

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने ईरान के दूतावास परिसर पर हवाई हमले के जवाब में हाल ही में कहा कि "पश्चिमी एशिया पूर्ण पैमाने पर संघर्ष का सामना कर रहा है।'' यह घटना पश्चिम एशिया या मध्य-पूर्व में व्यापक उथल-पुथल की एक झलक है, जो अस्थिरता, छद्म युद्ध और नव-औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं से भरी हुई है। क्षेत्र की रणनीतिक जटिलता भू-राजनीतिक, भू-आर्थिक और भू-धार्मिक चुनौतियों को समाहित करते हुए कई समस्याओं को जन्म देती है। फिलिस्तीन, लीबिया, सीरिया, इराक से लेकर यमन तक, प्रत्येक क्षेत्र में हुए संघर्ष का वैश्विक प्रभाव भारत और शेष विश्व पर पड़ता है। इस प्रकार तनाव कम करने की तत्काल आवश्यकता है।

1 अप्रैल 2024 को, इजराइल ने दमिश्क, सीरिया में ईरानी दूतावास परिसर पर हवाई हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप उसके कांसुलर सेक्शन की इमारत नष्ट हो गई। ये हवाई हमले इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच उस समय हुए जब इजराइल-हमास युद्ध और इजराइल-हेजबुल्लाह युद्ध भी चल रहा है। इस हमले के जवाब में, ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को इजराइल में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की।

* इस प्रकार, प्रथम दृष्टया परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान संकट काफी हद तक द्विध्रुवीय प्रतीत होता है, हालांकि इस द्विध्रुवीयता ने पश्चिम एशिया के इतिहास में उत्पन्न समस्याओं को और गहरा कर दिया है, जिसका विश्व भर में धीरे-धीरे प्रभाव पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में हुए कुछ घटनाक्रमों का उल्लेख करें तो उनमें ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में उग्रवादियों के गढ़ों पर किया गया एक निर्णायक हमला शामिल है, जिसमें कई लोग हताहत हुए। इस साहसिक आक्रमण ने विशेष रूप से सुन्नी उग्रवादी गुट जैश अल-अदल को निशाना बनाया। यह सोच-समझकर की गई कार्रवाई अपनी सीमाओं पर सुरक्षा खतरों से निपटने में ईरान की दृढ़ता को रेखांकित करती है, क्षेत्रीय गतिशीलता में बदलाव का संकेत देती है और क्षेत्र में बढ़ते तनाव के संबंध में चिंताएं उजागर करती है।
* इसके अलावा पश्चिम एशिया में अपनी वैध मांगों को पूरा करने की इच्छा रखने वाला इजराइल भी हाल ही में गाजा पट्टी के आस-पास हमास के नेतृत्व वाले फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों के साथ सशस्त्र संघर्ष में लगा हुआ है।
* यह सत्ता संघर्ष यमन, सीरिया और इराक में संघर्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जिससे तनाव बढ़ रहा है और पश्चिम एशिया में चल रही अस्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्तमान घटनाएं पश्चिम एशिया में दशकों से चली आ रही अस्थिरताओं की एक प्रस्तावना मात्र हैं। यह पिछले कुछ वर्षों में कई संकटों और संघर्षों में उलझा हुआ है, इसलिए ऐतिहासिक घटनाक्रम, संघर्ष के कारणों और भारत और विश्व भर में इसके प्रभाव के संभावित निहितार्थ पर गहराई से विचार करना अनिवार्य हो जाता है।

दशकों से अस्थिरता की स्थिति

* **इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष:** लंबे समय से चला आ रहा यह संघर्ष भूमि विवाद, सुरक्षा चिंताओं और फिलिस्तीनियों के अधिकारों से संबंधित है। इसके परिणामस्वरूप कई युद्ध और निरंतर तनाव उत्पन्न हुआ है और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयास किए गए है।
* **ईरान परमाणु समझौता:** 2015 में हस्ताक्षरित संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) का उद्देश्य प्रतिबंधों से राहत के बदले ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाना था। हालांकि, 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका के इससे अलग होने के बाद के तनाव ने क्षेत्रीय अस्थिरता में योगदान दिया है।
* **सीरियाई गृह युद्ध:** 2011 में शुरू हुए सीरियाई संघर्ष में आंतरिक गुटों, बाहरी हस्तक्षेप और मानवीय संकटों का एक जटिल तंत्र शामिल है। इसने रूस, ईरान, तुर्की और इजराइल सहित क्षेत्रीय शक्तियों को समानरूप से अपनी ओर आकर्षित किया है।
* **यमन संकट :** ईरान और सऊदी अरब के बीच क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के कारण यमन गृह युद्ध और भी तीव्र हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक अकाल और विस्थापन सहित मानवीय विभीषिका हुई है।
* **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) से संबंधित तनाव :** खाड़ी राज्यों के बीच तनाव, विशेष रूप से 2017 में सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और मिस्र द्वारा कतर को अलग-थलग करना, व्यापक क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और वैचारिक मतभेदों को दर्शाता है।
* **लेबनान की राजनीतिक अस्थिरता :** लेबनान को सांप्रदायिक विभाजन, ईरान और सऊदी अरब जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभाव और 2006 के इजराइल-लेबनान युद्ध के बाद की स्थिति के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

in फोकस

- जलवायु परिवर्तन तथा नागरिक अधिकार : गुणवत्तापूर्ण जीवन हेतु स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यकता
- सितवे एवं चाबहार बंदरगाह : पड़ोसी देशों में भारत की बंदरगाह विकास परियोजनाओं के रणनीतिक निहितार्थ
- भारत में खाद्य सुरक्षा : विनियमन एवं चुनौतियां

जलवायु परिवर्तन तथा नागरिक अधिकार

गुणवत्तापूर्ण जीवन हेतु स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यकता

हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा है कि नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद-21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है।

- न्यायालय के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों के संबंधों पर तेजी से ध्यान दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में, भारतीय संविधान के तहत प्रदत नागरिक अधिकारों के दायरे में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।
- सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण से जुड़े 'एम.के. रंजीत सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य' नामक मामले में दिया गया है। अपने निर्णय में न्यायालय द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित होने वाले स्वास्थ्य अधिकार, लैंगिक समानता तथा विकास आधारित अन्य मानवाधिकारों के संरक्षण पर भी प्रकाश डाला गया।
- न्यायालय का मानना है कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता देने से राज्यों को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। साथ ही, इससे जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों की पहचान करके इनके प्रभावों से भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के उपाय किए जा सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा के संबंध में नागरिक अधिकारों की संवैधानिक स्थिति

- **स्वस्थ जीवन का अधिकार:** अनुच्छेद-21 के तहत प्रदत्त जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार तथा अनुच्छेद-14 के तहत कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण द्वारा नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार की मान्यता प्राप्त है ताकि उन्हें स्वस्थ जीवनयापन के अवसर प्राप्त हो सकें।
- **राज्य को निर्देश:** अनुच्छेद-48A में कहा गया है कि, राज्य पर्यावरण की रक्षा करने तथा उसमें सुधार करने के साथ वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु प्रयास करेगा।
- इसी प्रकार, **अनुच्छेद 51-A (g)** के तहत पर्यावरण संरक्षण के संबंध में नागरिकों के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। इसके अनुसार नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वे जंगलों, झीलों, नदियों एवं वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखेंगे।
  - **अनुच्छेद-48A** तथा **अनुच्छेद 51-A** संबंधी प्रावधानों को 42वें संशोधन, 1976 द्वारा शामिल किया गया था।

स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार पर न्यायिक व्याख्याएं

- **एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987):** इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार को जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा माना था।
  - इसके बाद, उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों में लोगों को स्वच्छ हवा में साँस लेने, साफ पानी पीने और स्वस्थ जीवन जीने आदि अधिकारों को मान्यता दी गई है।
- **वीरेंद्र गौड़ बनाम हरियाणा राज्य (1994):** इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मान्यता दी गई कि 'स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार' 'स्वस्थ जीवन के अधिकार' का एक अभिन्न अंग है।
- **परमानंद कटारा बनाम भारतीय संघ (1989):** इसमें न्यायालय ने स्वास्थ्य के अधिकार को संबोधित करते हुए माना कि आपात स्थिति में मानव जीवन की रक्षा करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
- **अन्य मामले:** स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार से संबंधित 'सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य तथा अन्य (1991)' मामला।
  - आजीविका के अधिकार से संबंधित 'ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985)' मामला।

जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु उपाय

- **राष्ट्रीय उपाय**
  - **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC):** जलवायु शमन एवं अनुकूलन के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा में मजबूत अनुकूलन अनिवार्यता वाले प्रमुख राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं।
  - **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (NCEF):** इसकी स्थापना वर्ष 2010 में कोयला उत्पादन पर उपकर के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा पहल और अनुसंधान को वित्तपोषित करने के लिए की गई थी।
  - **पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताएं:** भारत का लक्ष्य 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता को 2005 के स्तर से 33-35% कम करना, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% बिजली क्षमता हासिल करना और वन आवरण विस्तार के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्मित करना है।

राष्ट्रीय परिदृश्य

न्यायपालिका
- निजी स्वामित्व वाली संपत्ति का पुनर्वितरण
- चुनावी उम्मीदवारों की निजता का अधिकार
- भ्रामक विज्ञापन केस : FMCGs कंपनियों तक जांच के दायरे का विस्तार

शासन प्रणाली
- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
- सामान्य मतदान प्रक्रिया में व्यवधान तथा चुनाव आयोग की शक्तियां
- पीएमएलए के तहत निर्णायक प्राधिकारी

राष्ट्रीय मुद्दे
- भारत में निर्विरोध चुनाव के कानूनी एवं व्यावहारिक पक्ष

समिति एवं आयोग
- अतुल गोयल की अध्यक्षता में तीन-सदस्यीय समिति का गठन

बैठक एवं सम्मेलन
- ICDRI का छठा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित

संविधान एवं राजव्यवस्था
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 (क)

केंद्र–राज्य संबंध
- आपदा राहत कोष पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद

न्यायपालिका

निजी स्वामित्व वाली संपत्ति का पुनर्वितरण

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) [Article 39(b)] की व्याख्या के लिए सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की।

- संविधान पीठ द्वारा इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा कि क्या राज्य नीति के निदेशक तत्त्व का यह प्रावधान सरकार को 'व्यापक सार्वजनिक भलाई' के लिए 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' (Material Resources of the Community) की आड़ में निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों के उपचार और पुनर्वितरण की अनुमति देता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 39(b)** संविधान के भाग IV (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) के अंतर्गत आता है। यह राज्य को समुदायों के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सुरक्षित करने की दिशा में नीति बनाने हेतु निर्देशित करता है।
- अनुच्छेद 39(b) राज्य पर 'समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस प्रकार वितरित करने की दिशा में नीति बनाने का दायित्व रखता है कि यह सार्वजनिक भलाई के लिए सर्वोत्तम हो'।
- राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, कानूनों को लागू करने के लिए एक प्रकार के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, परन्तु इन्हें किसी भी अदालत द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता।
- उच्चतम न्यायालय, **मुंबई में प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन** द्वारा महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (MHADA) में वर्ष 1986 में किए गए संशोधन द्वारा अध्याय VIII-A को शामिल करने को चुनौती देने वाले एक मामले की सुनवाई कर रहा है।
- इसमें दावा किया गया है कि **अध्याय VIII-A के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत** संपत्ति मालिकों के **समानता के अधिकार का उल्लंघन** करते हैं।
- मुंबई के प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन समेत कई याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दलील दी गई है कि संविधान के अनुच्छेद-39(b) की आड़ में सरकार निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती।
- **वर्ष 1977 के बाद** से शीर्ष अदालत ने कई मौकों पर अनुच्छेद 39(b) की व्याख्या पर विचार किया है। उदाहरण- **कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी (1977) मामला**।
- बाद के निर्णयों में इस व्याख्या पर भ्रम की स्थिति के कारण मामला वर्ष **2002 में 9-न्यायाधीशों की पीठ** को भेजा गया।
- मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को **संविधान के अनुच्छेद-19(1)(f) और अनुच्छेद-31** के तहत एक **मौलिक अधिकार** के रूप में मान्यता दी गई थी।
- **वर्ष 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम** के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर **अनुच्छेद-300A के तहत संवैधानिक अधिकार** का दर्जा प्रदान कर दिया गया।

चुनावी उम्मीदवारों की निजता का अधिकार

9 अप्रैल, 2024 को उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय दिया कि चुनाव में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों को 'निजता का अधिकार' प्राप्त है और उन्हें मतदाताओं को अपने व्यक्तिगत जीवन तथा अपनी संपत्ति के बारे में प्रत्येक विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

- यह ऐतिहासिक निर्णय **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं के दायरे पर स्पष्टता प्रदान करता है और व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के साथ पारदर्शिता को संतुलित करने के महत्व को रेखांकित करता है।
- यह मामला **अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक** द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है, जिसमें कथित तौर पर अपने हलफनामे में तीन वाहनों को संपत्ति के रूप में घोषित करने में विफल रहने के कारण **तेजू विधानसभा क्षेत्र** में उनके चुनाव को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
  - उच्च न्यायालय ने विधायक के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील की गई।

सार्वजनिक नीति

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD Act, 2016) के अपर्याप्त कार्यान्वयन पर निराशा व्यक्त की।

- यह देखते हुए कि RPwD Act का **कार्यान्वयन 'निराशाजनक' स्थिति** में है, न्यायालय ने **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** को विस्तृत तौर पर विचार करने तथा न्यायालय को अपडेट प्रदान करने का निर्देश दिया।
- अधिनियम की **धारा 79** के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, त्रिपुरा, यूपी और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ जैसे राज्यों ने **आयुक्त नियुक्त नहीं** किए हैं।
- इसी प्रकार, कुछ राज्यों ने **धारा 88** (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य निधि) के तहत कोई **फंड तैयार नहीं** किया है। इनमें- गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दमन दीव, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे राज्य शामिल हैं।
- अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल; छत्तीसगढ़ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दमन दीव जैसे राज्यों ने **धारा 84 और 85** के तहत त्वरित सुनवाई और लोक अभियोजकों के लिए विशेष अदालतों का गठन नहीं किया है।
- केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, दमन-दीव आदि में **धारा 6(2) (ii)** (दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए) के तहत **दिव्यांगता के अनुसंधान हेतु कोई समिति गठित नहीं की गई** है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के संदर्भ में

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को **2016 में अधिनियमित** किया गया था और यह 2017 में लागू हुआ था।
- यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और संबंधित मामलों पर **संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन** को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। भारत ने वर्ष **2007 में इस पर हस्ताक्षर** किए थे।
- इस अधिनियम ने **विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995** का स्थान लिया।
- इस अधिनियम में दिव्यांगता को एक **विकसित और गतिशील अवधारणा** के आधार पर परिभाषित किया गया है और दिव्यांगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
  - **विकलांगता के प्रकारों** में कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, सेरेब्रल पाल्सी, एसिड अटैक पीड़ित, अंधापन, बहरा, विशिष्ट सीखने की विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, पार्किंसंस रोग, हीमोफिलिया आदि शामिल हैं।
- अधिनियम के तहत **बेंचमार्क विकलांगता** (Benchmark-Disability) से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है।
  - जिन व्यक्तियों में कम से कम **40% विकलांगता होना प्रमाणित** है, उन्हें 'बेंचमार्क विकलांगता' के रूप में परिभाषित किया गया है।
- अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों को **शिक्षा और सरकारी नौकरियों** में अब तक दिए जा रहे **3% आरक्षण** की व्यवस्था को बढ़ाकर 4% कर दिया गया है।
  - **बेंचमार्क विकलांगता** वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त **उच्च शिक्षण संस्थानों में सीटों में 5% आरक्षण** दिया गया है।
- अधिनियम की **धारा 92** के अनुसार, विकलांग लोगों के खिलाफ किया गया अत्याचार दंडनीय है।
  - इस खंड का **उद्देश्य** विकलांग लोगों को कानूनी सुरक्षा देना है।
- कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों, या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या विनियमन का उल्लंघन करता है, उसे **छह महीने तक कारावास और/या 10,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों से** दंडित किया जाएगा।

रिपोर्ट एवं सूचकांक

राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक

भारत में सौर ऊर्जा क्षमता में गिरावट की प्रवृत्ति: IMD अध्ययन

हाल ही में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया अध्ययन 'मौसम' नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ। इस अध्ययन से देश में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में अत्यधिक कमी की प्रवृत्ति का पता चला है।

- IMD द्वारा प्रकाशित अध्ययन का शीर्षक **''भारत में सतह आधारित 'इन-सीटू' अवलोकनों का उपयोग करके सौर विकिरण में जलवायु विज्ञान एवं दीर्घकालिक रुझान को समझना''** था।
- अध्ययन में **'एयरोसोल के भार में वृद्धि'** को सौर विकिरण में कमी का कारण माना गया है। कार्बन उत्सर्जन से निकलने वाले महीन कणों, जीवाश्म ईंधन के दहन तथा धूल एवं बादल की उपस्थिति से एयरोसोल के भार में वृद्धि हुई है।
- अध्ययन के अनुसार, **एरोसोल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित** करते हैं, इससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। यह स्थिति अंतिम रूप से सौर पैनलों द्वारा प्राप्त की जाने वाले सौर विकिरण में कमी के रूप में परिलक्षित होती है।
- अध्ययन में वर्ष **1985 से 2019 तक के निरंतर सौर विकिरण रिकॉर्ड वाले 13 IMD स्टेशनों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग** किया गया था।
- भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी **नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य** रखा है। हालांकि, सौर विकिरण में देखी गई गिरावट से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक

'टुवर्ड्स ए रीजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी: मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी' रिपोर्ट

हाल ही में, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (IUCN) द्वारा 'टुवर्ड्स ए रीजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी: मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी' नामक रिपोर्ट जारी की गई है।

- यह रिपोर्ट रीजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी यानी पुनरुत्पादक नीली अर्थव्यवस्था के लिए एक स्पष्ट परिभाषा और इसके संस्थापक सिद्धांतों का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है।
- 'रीजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी' (RBE) एक आर्थिक मॉडल है। यह महासागरीय तथा तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के प्रभावी पुनरुत्पादन एवं संरक्षण को टिकाऊ आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ता है।
- **RBE के संस्थापक सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल होंगे:**
  - प्राथमिकताओं के रूप में समुद्री और तटीय पारिस्थितिक प्रणालियां, समुद्री संसाधनों एवं प्राकृतिक पूंजी की सुरक्षा, पुनर्स्थापना, लचीलापन और पुनरुत्पादन।
  - प्रभावित आबादी के समावेशन, एकजुटता, कल्याण और लचीलेपन को प्राथमिकता देना।
  - वैज्ञानिक आकलन के साथ समावेशी और सहभागी गवर्नेंस प्रणाली।
  - तटीय आबादी तथा देशज लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आदि।
- **निम्नलिखित गतिविधियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है:**
  - कार्बन कटौती संबंधी उद्देश्यों के अनुरूप न होने के कारण तेल उत्पादन गतिविधियां।
  - समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा होने के कारण गहरे समुद्र में खनन।

'रीजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी' के लिए सिफारिशें

- पुनरुत्पादक गतिविधियों के लिए वित्तपोषण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ग्लोबल साउथ में विज्ञान और नवाचार के आधार का विस्तार किया जाना चाहिए।
- समुद्री स्तर पर उपाय करने के लिए स्थानीय हितधारकों को सशक्त बनाना चाहिए।

RBE को बढ़ावा देने वाली पहलें

- **वैश्विक पहलें:** IUCN की नेचर 2030, ग्रेट ब्लू वॉल इनीशिएटिव, स्वच्छ समुद्र अभियान और केपटाउन मेनिफेस्टो।
- **भारतीय पहलें:** मैरिटाइम इंडिया विजन 2030, डीप ओशन मिशन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन आदि।

सामाजिक परिदृश्य

स्वास्थ्य

- उच्चतम न्यायालय द्वारा गर्भपात की अनुमति

अतिसंवेदनशील वर्ग

- ट्रांसजेंडरों की भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध

सामाजिक कल्याण

- 'नवचेतना': आंगनवाड़ियों के लिए गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम
- आधारशिला: 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा
- चाइल्डकेयर लीव से इनकार करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन

महिला सशक्तीकरण

- जापान के 'वुमेनोमिक्स' कार्यक्रम से भारत को सीख

स्वास्थ्य

उच्चतम न्यायालय द्वारा गर्भपात की अनुमति

22 अप्रैल, 2024 को उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न की 14 वर्षीय पीड़िता को लगभग 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी।

- ऐसा करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 में 24 सप्ताह की ऊपरी सीमा को पार कर लिया है।
- हालांकि 29 अप्रैल, 2024 को उच्चतम न्यायालय ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया क्योंकि 30 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करना पीडिता के लिए अत्यधिक जोखिम भरा था और इससे चिकित्सकीय जटिलताएं उत्पन्न हो सकती थीं।

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 2021 की मुख्य विशेषताएं

- **गर्भावस्था के 20 सप्ताह से पूर्व गर्भपात:** अधिनियम के अनुसार 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए केवल 'एक डॉक्टर' की चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता होगी।
- **गर्भावस्था के 24वें सप्ताह तक या उसके बाद गर्भपात:** अधिनियम में कुछ परिस्थितियों में महिलाओं के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात कराना वैध बनाया गया है। इसके लिए 'दो डॉक्टरों' की चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता होगी।
  - इसमें बलात्कार की शिकार तथा कमजोर महिलाओं (दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग आदि) को शामिल किया गया है।
- **राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन:** अधिनियम में प्रावधान है कि 24 सप्ताह के बाद गर्भपात कराने का निर्णय लेने के लिए एक राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- **गुमनामी:** जिस महिला की गर्भावस्था समाप्त हो गई है उसका नाम और अन्य विवरण उस समय लागू किसी भी कानून में अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर प्रकट नहीं किया जाएगा।
- **वैवाहिक और आयु मानदंड:** अविवाहित महिलाएं भी उपर्युक्त शर्तों के तहत गर्भपात करा सकती हैं क्योंकि इसमें पति-पत्नी की सहमति की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है। हालाँकि, यदि महिला नाबालिग है, तो अभिभावक की सहमति आवश्यक है।
- **जानबूझकर गर्भपात कराना:** भारतीय दंड संहिता की धारा 312 जानबूझकर गर्भपात करवाने को एक अपराध मानती है।

अतिसंवेदनशील वर्ग

ट्रांसजेंडरों की भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध

10 अप्रैल, 2024 को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी एक आदेश के माध्यम से, पुणे के पुलिस आयुक्त द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा ट्रैफिक सिग्नल, निजी आवास और अन्य सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों आदि में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

- इसी तरह का प्रतिबंध नागपुर के पुलिस आयुक्त द्वारा वर्ष 2023 में भी लगाया गया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- **प्रतिबंध की संवैधानिक वैधानिकता:** यह प्रतिबंध विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय को अनुच्छेद 14 के तहत प्राप्त समानता के अधिकार को सीमित करता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नही किया जाएगा।
  - यह प्रतिबंध विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिंग समानता के अधिकार (अनुच्छेद 15) के विरुद्ध भी है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

कल्याणकारी योजनाएं

सीडीपी–सुरक्षा प्लेटफॉर्म

हाल ही में, भारत सरकार ने बागवानी सब्सिडी के लिए सीडीपी-सुरक्षा (CDP-SURAKSHA) नामक प्लेटफॉर्म पेश किया है, जिसका लक्ष्य बागवानी के विकास को बढ़ावा देना और सब्सिडी वितरण को सुव्यवस्थित करना है।

- **सीडीपी-सुरक्षा मूलतः** एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सुरक्षा (SURAKSHA) का अर्थ है 'एकीकृत संसाधन आवंटन, ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए प्रणाली'।
- यह प्लेटफॉर्म **नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया** (NPCI) से ई-रुपी वाउचर का उपयोग करके किसानों को उनके बैंक खाते में त्वरित सब्सिडी प्रदान करने की अनुमति देगा।
- इस प्लेटफॉर्म की **विशेषताओं** में शामिल हैं- पीएम-किसान के साथ डेटाबेस एकीकरण, एनआईसी से क्लाउड-आधारित सर्वर स्पेस, यूआईडीएआई सत्यापन, ई-रुपी एकीकरण, स्थानीय सरकारी निर्देशिका (LGD), सामग्री प्रबंधन प्रणाली, जियोटैगिंग और जियो-फेंसिंग।
- **पुरानी व्यवस्था** में किसान को रोपण सामग्री स्वयं खरीदनी पड़ती थी। इसके पश्चात उन्हें सब्सिडी जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना होता था।
  - **नई व्यवस्था** के तहत, सीडीपी-सुरक्षा मंच किसानों को रोपण सामग्री खरीदने के समय अग्रिम सब्सिडी प्रदान करेगा। विक्रेता, जो किसानों को रोपण सामग्री की आपूर्ति करेंगे, उन्हें अपना भुगतान तभी प्राप्त होगा जब किसान अपने ऑर्डर की डिलीवरी सत्यापित करेंगे।
- **इस कदम का उद्देश्य** भारत के बागवानी क्षेत्र, जो कृषि सकल मूल्यवर्धन (GAV) में लगभग एक तिहाई योगदान देता है, के विकास को प्रोत्साहित करना है।

सीडीपी-सुरक्षा मंच की कार्यप्रणाली

- **पहुंचः** यह मंच किसानों, विक्रेताओं, कार्यान्वयन एजेंसियों (IA), क्लस्टर विकास एजेंसियों (CDA) और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) के अधिकारियों के लिए सुलभ है।
- **ऑर्डर प्लेसमेंटः** किसान अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग-इन कर सकते हैं और बीज, अंकुर तथा पौधों जैसी रोपण सामग्री के लिए ऑर्डर दे सकते हैं।
- **लागत साझा करनाः** ऑर्डर देने के पश्चात, किसानों को लागत के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी राशि स्वचालित रूप से प्रदर्शित होती है।
- **ई-रुपी वाउचरः** किसान द्वारा भुगतान करते समय एक ई-रुपी वाउचर जेनरेट होता है, जो रोपण सामग्री की आपूर्ति करने वाले विक्रेता को प्राप्त होता है।
- **सत्यापनः** किसानों को अपने खेतों की जियो-टैग की गई तस्वीरों और वीडियो के साथ ऑर्डर की गई रोपण सामग्री की प्राप्ति को सत्यापित करना होगा।
- **भुगतानः** एक बार सत्यापित होने के बाद, कार्यान्वयन एजेंसियों (IA) द्वारा विक्रेता को भुगतान जारी किया जाएगा।
- **चालान अपलोड करना आवश्यकः** इसके पश्चात, विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म पर भुगतान का चालान अपलोड करना होता है।

ईशान पहल

भारत ने हवाई यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए पूरे देश में फैले अपने चार हवाई क्षेत्र क्षेत्रों को एक में एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

- इस क्रम में हाल ही में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने 'नागपुर में इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट' (ISHAN) पहल के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु रुचि आधारित अभिव्यक्तियों की मांग की।
- यह कदम विमानन उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, इसके तहत वर्ष 2030 तक घरेलू यात्री यातायात को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इस परियोजना के लिए समान प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन, मौजूदा प्रक्रियाओं में परिवर्तन, हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के पुनर्प्रशिक्षण एवं नीति निर्माण की आवश्यकता होगी।
- ईशान (ISHAN) एक एकीकरण पहल है, जिसका उद्देश्य हवाई यातायात प्रबंधन (ATM) को परिष्कृत एवं मजबूत करना है। इसमें भारत के चार एयरस्पेस क्षेत्रों को एकल प्राधिकरण में एकीकृत किया जाएगा।
- वर्तमान में भारतीय एयर स्पेस 4 एयर स्पेस (मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में) और एक सब-एयर स्पेस गुवाहाटी में विभाजित है, इन सभी को अलग-अलग प्रबंधित किया जाता है।
- विमानन उद्योग में एक 'उड़ान सूचना क्षेत्र' हवाई क्षेत्र का एक निर्दिष्ट क्षेत्र होता है, जिसके द्वारा 'उड़ान सूचना सेवा' और 'चेतावनी सेवा' (ALRS) प्रदान की जाती है।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India- AAI) नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- AAI की स्थापना 1 अप्रैल, 1995 को तत्कालीन राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण तथा भारतीय अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण का विलय करके की गई थी।
- यह स्थल एवं हवाई क्षेत्र दोनों पर नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव तथा प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। ■

विरासत एवं संस्कृति

व्यक्तित्व

- भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव
- महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती

विरासत स्थल एवं स्मारक

- स्मारकों और स्थलों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस

उत्सव एवं पर्व

- बोहाग बिहू पर्व

पुरातात्विक साक्ष्य

- कच्छ में हड़प्पाकालीन बस्ती की खोज

व्यक्तित्व

भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव

21 अप्रैल, 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में महावीर जयंती के अवसर पर भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। इसे 'अहिंसा महोत्सव' के रूप में भी आयोजित किया गया।

- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया।
- इस महोत्सव की योजना और आयोजन के लिए 'भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति' का गठन किया गया है।
- इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भगवान महावीर के जीवन और उनके अहिंसा और दयालुता के सिद्धांतों को समर्पित करके मानवता को उनके संदेशों की महत्वपूर्णता समझाना है।

जीवन परिचय

- महावीर, जिन्हें वर्धमान (Vardhamana) के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे।
- जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर सम्प्रदाय के अनुसार, भगवान महावीर का जन्म चैत्र माह के 13वें दिन राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र के रूप में हुआ था।
- अलग-अलग मान्यताओं के अनुसार भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व या 615 ईसा पूर्व बताया जाता है।
- उनके माता-पिता 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के भक्त थे।
- महावीर ने लगभग 30 वर्ष की आयु में सभी सांसारिक संपत्तियों को त्याग दिया और एक तपस्वी बनकर आध्यात्मिक जागृति की खोज में घर छोड़ दिया।
- महावीर ने साढ़े 12 वर्षों तक गहन ध्यान और कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्होंने सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण (जैन धर्म के त्रि-रत्न) के माध्यम से केवल्य ज्ञान (सर्वज्ञान) की प्राप्ति की।

शिक्षाएं और योगदान

- उन्होंने वेदों के प्रमाणिकता पर सवाल उठाया और जनता को सांसारिक अस्तित्व के परीक्षणों और क्लेशों से मुक्ति पाने का सुझाव दिया।
- यह ब्राह्मणवादी स्थिति के विपरीत था, जिसमें किसी व्यक्ति का अस्तित्व एक विशिष्ट जाति या लिंग में उसके जन्म से निर्धारित होता था।
- उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ के समय से चले आ रहे चार महाव्रतों में एक और व्रत (ब्रह्मचर्य) जोड़ा।
- पांच महाव्रत निम्नलिखित हैं:
  1. अहिंसा (हिंसा न करना)
  2. सत्य (सच बोलना)
  3. अस्तेय (चोरी न करना)
  4. अपरिग्रह (धन का संग्रह न करना)
  5. ब्रह्मचर्य (इंद्रिय निग्रह करना)।
- अंतिम तीर्थंकर के रूप में, उन्होंने तीर्थ (धार्मिक आदेश) को पुनर्जीवित किया और इस आदेश को जैन संघ (आदेश) के रूप में जाना जाता है।
- उनकी शिक्षाओं को उनके प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम (Indrabhuti Gautama) ने जैन आगम (Jain Agamas) के रूप में संकलित किया था।
- उन्होंने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया, ताकि आम लोग उनकी शिक्षाओं को समझ सकें क्योंकि संस्कृत कई लोगों को समझ में नहीं आती थी।
- उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के पास पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया।

महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती

11 अप्रैल, 2024 को ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। ज्योतिबा फुले भारत के अग्रणी समाज सुधारक, शिक्षक, विचारक, जाति-विरोधी और लेखक थे।

आर्थिक विकास एवं परिदृश्य

मुद्रा एवं बैंकिंग

- पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए आरबीआई के ड्राफ्ट नियम
- भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम मौद्रिक नीति रिपोर्ट

करारोपण

- भारत सरकार के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि

वित्त क्षेत्र

- नियामक सैंडबॉक्स पर ट्राई की सिफारिशें
- एफआईआई को ग्रीन बांड में निवेश की अनुमति
- IRDAI द्वारा स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आयु सीमा समाप्त

व्यापार एवं निवेश

- भारत ने डब्ल्यूटीओ में चावल के लिए 'पीस क्लॉज' लागू किया

अवसंरचना

- पिन कोड MH-1718: अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

- FSSAI द्वारा मसाला मिश्रण उत्पादों की गुणवत्ता की जांच

मुद्रा एवं बैंकिंग

पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए आरबीआई के ड्राफ्ट नियम

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान एग्रीगेटर्स (PA) के बेहतर विनियमन हेतु दो परामर्श-पत्र जारी किये गए है।

- इनमें से, **प्रथम परामर्श** पत्र ऑफलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स (PA) की गतिविधियों से संबंधित है। जबकि दूसरा अपने ग्राहक को जानें (KYC), ऑनबोर्ड व्यापारियों के उचित परिश्रम और एस्क्रो खातों में संचालन के लिए निर्देशों का विस्तार करके पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा को मजबूत करने का प्रस्ताव करता है।
- **वर्तमान समय** में देश में मौजूदा दिशानिर्देश केवल ई-कॉमर्स साइटों और अन्य ऑनलाइन माध्यमों की गतिविधियों को कवर करते हैं। **दूसरी तरफ, नवीनतम मसौदा** दिशानिर्देशों में इन विनियमों को ऑफलाइन स्थानों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है, जिसमें निकटता या आमने-सामने लेनदेन शामिल है।
- **पेमेंट एग्रीगेटर** (PA) ऐसी संस्थाएं हैं, जो व्यापारियों की ओर से ग्राहकों से भुगतान एकत्र करके ऑनलाइन लेनदेन की सुविधा प्रदान करती हैं। वे खरीदार, विक्रेता और भुगतान गेटवे के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं।
- **उदहारण:** रेजरपे (Razorpay), इंस्टामोजो (Instamojo), कैशफ्री (Cashfree), सीसीएवेन्यू (CcAvenue), पेयू (PayU), मोबिक्विक (Mobikwik), पेटीएम (Paytm) और पेपल (PayPal) इत्यादि।
- **पेमेंट एग्रीगेटर के कार्य**
  - **भुगतान एकत्र करना:** वे भागीदारों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और अधिकारियों जैसे विभिन्न हितधारकों को भुगतान वितरित करने में भी सक्षम बनाते हैं।
  - **निपटान:** पेमेंट एग्रीगेटर अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्डलेस EMI, UPI, बैंक ट्रांसफर, ई-वॉलेट और ई-मैंडेट जैसे विभिन्न भुगतान विधियों को स्वीकार करने में सक्षम बनाते हैं।
  - **सुरक्षा:** भुगतान एग्रीगेटर्स संवेदनशील ग्राहक जानकारी की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन और अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करके लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
  - **एकीकरण:** वे एपीआई (API) और प्लगइन्स (Plugins) प्रदान करते हैं, जिन्हें व्यापारी आसानी से भुगतान स्वीकार करने के लिए अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप में एकीकृत कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम मौद्रिक नीति रिपोर्ट

3-5 अप्रैल, 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रथम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में, MPC द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति के लगातार 4% के लक्ष्य से ऊपर बने रहने के कारण नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया।

- यह लगातार सातवीं बैठक है जब एमपीसी ने रेपो रेट पर यथास्थिति बनाए रखी है।
- बैठक में **स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 6.25% तथा सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर एवं बैंक दर 6.75%** पर बनाए रखने का निर्णय लिया गया।
  - **रेपो रेट** वह दर है जिसके माध्यम से आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।
- इन **निर्णयों का उद्देश्य** आर्थिक विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को +/- 2% के बैंड के भीतर 4% के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति के मध्यम अवधि के लक्ष्य के साथ संरेखित करना है।
- आरबीआई के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 7% बढ़ने का अनुमान है, जबकि खुदरा मुद्रास्फीति 4.5% रहने की संभावना है।

मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में

- RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC), **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934** के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध व संगठन

संधि एवं समझौते
- बाह्य अंतरिक्ष संधि से संबंधित UNSC प्रस्ताव पर रूस का वीटो

वैश्विक पहलें
- हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली को पुनः सक्रिय करने का निर्णय
- WHO द्वारा 'रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर' का शुभारंभ
- इंटरसेक्स व्यक्तियों के अधिकारों पर यूएनएचआरसी का प्रस्ताव

बैठक एवं सम्मेलन
- सूडान एवं पड़ोसी देशों हेतु अंतरराष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन

संगठन एवं फोरम
- क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खाड़ी सहयोग परिषद का विजन

भारत के पड़ोसी देश
- बिम्सटेक चार्टर पर नेपाल की सहमति

विदेश नीति
- विभिन्न देशों में डिफेन्स अटैशे की तैनाती
- दक्षिण चीन सागर में भारत का दृष्टिकोण

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
- सिंथेटिक ओपिओइड प्रीकर्सर 'फेंटानिल' पर वार्ता
- मेक्सिको दूतावास पर इक्वाडोर की छापेमारी

मानचित्र के माध्यम से
- अटाकामा मरुस्थल में जैवमंडल की खोज

संधि एवं समझौते

बाह्य अंतरिक्ष संधि से संबंधित UNSC प्रस्ताव पर रूस का वीटो

24 अप्रैल, 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने 'बाह्य अंतरिक्ष संधि' (Outer Space Treaty) पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्ताव को वीटो करने के लिए रूस की सख्त आलोचना की।

- सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में देशों पर यह बाध्यकारी दायित्व डाला गया था कि देशों को परमाणु हथियारों सहित सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) को अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित नहीं करना चाहिए।

- यह मसौदा प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित किया गया था।
- अमेरिका और जापान द्वारा **लगभग 6 सप्ताह की बातचीत के बाद** 'बाह्य अंतरिक्ष संधि' से संबंधित मसौदा प्रस्ताव पर मतदान कराया गया। इसके **पक्ष में 13 वोट** पड़े, जबकि **चीन अनुपस्थित** रहा।
- **अमेरिका एवं जापान जैसे देशों का मानना है** कि 'आउटर स्पेस' में किसी भी प्रकार की हथियारों की होड़ को व्यापक रूप से प्रतिबंधित करने के लिए यह कदम आवश्यक है।
- पृथ्वी के **वायुमंडल से बाहर का क्षेत्र 'बाह्य अंतरिक्ष'** (Outer Space) कहलाता है। वायुमंडल और 'बाह्य अंतरिक्ष' को पृथक करने वाली काल्पनिक रेखा को कार्मन रेखा (Karman Line) कहा जाता है।
- आमतौर पर, **'बाह्य अंतरिक्ष'** और ब्रह्मांड शब्द को लगभग समान अर्थों में उपयोग किया जाता है; किंतु सूक्ष्म स्तर पर, 'बाह्य अंतरिक्ष' केवल ग्रहों के बीच के क्षेत्र को संदर्भित करता है, जबकि **ब्रह्मांड** में ग्रहों को भी शामिल किया जाता है।

बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967

- संयुक्त राष्ट्र की **'बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967' एक अंतरराष्ट्रीय समझौता** है, जो सदस्य देशों को बाहरी अंतरिक्ष के केवल शांतिपूर्ण उपयोग को मान्यता देता है।
- इसके आधार पर चंद्रमा एवं अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष की खोज तथा उपयोग से संबंधित देशों की **गतिविधियों को नियंत्रित** किया जाता है। भारत द्वारा वर्ष 1982 में इस संधि का अनुमोदन (Ratified) किया गया था।
- बाह्य अंतरिक्ष को नियंत्रित करने वाली **संयुक्त राष्ट्र की अन्य संधियां:**
  - संकट में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने, सहायता पहुंचाने और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए **वर्ष 1968 का बचाव समझौता** (Rescue Agreement)।
  - **वर्ष 1972 का लाइबिलिटी कन्वेंशन** (Liability Convention), जिसमें प्रावधान है कि कोई भी देश पृथ्वी की सतह पर अपनी गतिविधियों तथा अंतरिक्ष में अपने विमानों के कारण होने वाली क्षति के रूप में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

पर्यावरण एवं जैव विविधता

जलवायु परिवर्तन

- हिमालय में हिमानी झीलों के आकार में वृद्धि
- विश्व का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप : यूरोप
- चौथा ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग

सम्मेलन एवं बैठक

- आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

पर्यावरण संरक्षण

- नाबार्ड द्वारा हरित वित्तपोषण
- हरित क्रेडिट प्रोग्राम से संबंधित दिशानिर्देश

ऊर्जा एवं सतत विकास

- सौर पीवी सेलों का निर्माण
- भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता

पर्यावरणीय अवनयन व प्रदूषण

- चेन्नई की झीलों में फॉरएवर केमिकल्स

आपदा प्रबंधन

- भारत में मृदा क्षरण

जलवायु परिवर्तन

हिमालय में हिमानी झीलों के आकार में वृद्धि

22 अप्रैल 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन(इसरो) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, हिमालय क्षेत्र में कुल हिमानी झीलों (Glacial Lakes) में से 27% हिमानी झीलों का विस्तार हो रहा है।

मुख्य बिन्दु

- **अवधि:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 1984 से 2023 की अवधि के दौरान भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जलग्रहण क्षेत्रों की दीर्घकालिक उपग्रह छवियों का अध्ययन किया हैं।

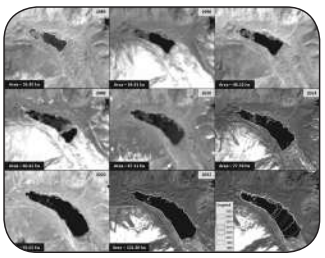

- **संख्या:** 2016-17 के दौरान पहचानी गई 10 हेक्टेयर से बड़ी 2,431 झीलों में से 676 हिमनदी झीलों का 1984 के बाद से उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।
- **विस्तार:** 676 झीलों में से 601 का विस्तार दोगुने से अधिक हो गया है।
  - इनमें से 10 झीलों का विस्तार 1.5 से दो गुना और 65 झीलों का 1.5 गुना हो गया है।
- **अवस्थिति:** इन 676 झीलों में से 130 भारत के भीतर स्थित हैं, जिनमें से 65 सिंधुनदी घाटी, सात गंगा नदी घाटी और 58 ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित हैं।
- **ऊंचाई (Elevation):** ऊंचाई-आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि 314 झीलें 4,000-5,000 मीटर की सीमा में और 296 झीलें 5,000 मीटर से ऊपर स्थित हैं।

हिमानी झीलें

- ग्लेशियरों के पिघलने से बनी जलराशियों को हिमानी झीलें कहा जाता है। ग्लेशियरों के पिघलने से हिमालय क्षेत्र में नई झीलों का निर्माण हो रहा है और मौजूदा झीलों का विस्तार होता है।
- **प्रकार:** हिमानी झीलों को उनकी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:
  - मोराइन- डैम्ड (moraine-dammed)
  - आइस-डैम्ड (ice-dammed)
  - अपरदन (erosion)
  - अन्य हिमानी झीलें।
- **उपयोगिता:** हिमानी झीलें हिमालय क्षेत्र में मीठे पानी के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही ये हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियों के लिए जल स्रोत का भी कार्य करती हैं।
- **जोखिम:** हिमानी झीलें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स (Glacial Lake Outburst Floods - GLOF) जैसे महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती हैं, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड

- **परिचय:** ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) एक प्रकार की तीव्र बाढ़ है यह तब उत्पन्न होती है जब ग्लेशियल झील युक्त बांध टूट जाता है। ये बहुत तीव्रता से घटित होती है, तथा इनकी अवधि कुछ घण्टों से लेकर कुछ दिनों तक होती है।
- **प्रभाव:** इनके कारण नदियों के निचले भागों में अचानक अति तीव्र जल बहाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें, बहुधा जल के परिमाण के अनुसार वृद्धि होती रहती है।
- **सुभेद्यता:** वैश्विक स्तर पर GLOFs के प्रति सुभेद्य लोगों की कुल संख्या का एक-तिहाई हिस्सा भारत और पाकिस्तान में निवास करती हैं।
  - भारत में तीस लाख लोगों को हिमनदी झीलों के कारण बाढ़ का खतरा है, जो विश्व के किसी एक देश में लोगों की सबसे अधिक संख्या हैं।

अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान

- शून्य अंतरिक्ष मलबा
- ब्रह्मांड का त्रि-आयामी मानचित्र
- आदित्य मिशन
- स्वीडन और स्लोवेनिया आर्टेमिस समझौते में शामिल

स्वास्थ्य विज्ञान

- यूविशोल-एस

नवीन प्रौद्योगिकी

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं चुनाव

रक्षा विज्ञान

- DURGA-2
- अग्नि-प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण

जैव-प्रौद्योगिकी

- आनुवंशिक प्रोफाइलिंग
- कैंसर की चिकित्सा हेतु जीन थेरेपी

अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान

शून्य अंतरिक्ष मलबा

हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation - ISRO) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, PSLV-C58/XPoSat मिशन ने पृथ्वी की कक्षा में व्यावहारिक रूप से शून्य मलबा छोड़ा है।

मुख्य बिन्दु

- **अंतिम चरण:** PSLV-C58/XPoSat मिशन में उपयोग किए गए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (Polar Satellite Launch vehicle - PSLV) के अंतिम चरण को एक प्रकार के कक्षीय स्टेशन में बदल दिया गया था।
- **कक्षीय स्टेशन:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार, इस कक्षीय स्टेशन को पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल-3 (PSLV Orbital Experimental Module-3) कहा जाता है।
- **पुनः-प्रवेश:** मिशन पूरा होने के बाद इसके बचे हुए अंशों के पृथ्वी की उपरी कक्षा में तैरने के बजाय प्रक्षेपण यान पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः-प्रवेश कर गया।

अंतरिक्ष मलबा

- **परिचय:** अंतरिक्ष मलबा, पृथ्वी की कक्षा में मानव निर्मित अनुपयोगी वस्तुएं अंतरिक्ष मलबे के रूप में जानी जाती हैं।
- **अंतरिक्ष मलबे में शामिल वस्तुएं:** इनमें प्रक्षेपण के समय उपयोग किए गए रॉकेट, निष्क्रिय उपग्रह, एंटी-सैटेलाइट सिस्टम (ASAT) से उत्पन्न पदार्थ तथा अन्य मानव निर्मित अवयव शामिल रहते हैं।
- **निगरानी:** यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस सर्विलांस नेटवर्क द्वारा 10 सेमी (4 इंच) से बड़े अंतरिक्ष मलबे के 15,000 से अधिक टुकड़ों की निगरानी की जा रही थी।
- **संख्या:** यह अनुमान लगाया गया है कि अंतरिक्ष मलबे में 1 से 10 सेमी (0.4 और 4 इंच) के बीच के लगभग 200,000 टुकड़े हैं तथा 1 सेमी से छोटे लाखों टुकड़े हो सकते हैं।
- **चुनौती:** चूंकि मलबे के ये टुकड़े और अंतरिक्ष यान दोनों ही बहुत तेज गति से पृथ्वी की कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए अंतरिक्ष यान के साथ कक्षीय मलबे के एक छोटे से टुकड़े का प्रभाव भी एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है।

अंतरिक्ष मलबे की समस्या से निपटने हेतु भारत के प्रयास

- **IS4OM:** इसरो द्वारा वर्ष 2022 में सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट (IS4OM) स्थापित किया गया है।
  - IS4OM का उद्देश्य टकराव के खतरों से निपटने के लिए अंतरिक्ष की वस्तुओं (Space Objects) की निरंतर निगरानी करना, अंतरिक्ष मलबे के विकास की संभावनाओं का आकलन करना तथा अंतरिक्ष मलबे से उत्पन्न जोखिमों को कम करना है।
- **नेत्र परियोजना:** भारत द्वारा नेत्र परियोजना (NETRA project) प्रारम्भ की गई है। यह भारतीय उपग्रहों को मलबे तथा अन्य अंतरिक्ष खतरों से सुरक्षित करने के लिए ISRO द्वारा स्थापित एक 'प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली' (Early Warning System) है।

अंतरिक्ष मलबे की समस्या से निपटने हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रयास

- **रिमूव डेब्रिस (Remove Debris):** यूरोपीय संघ के यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) की रिमूव डेब्रिस (RemoveDebris) पहल द्वारा पृथ्वी की निम्न कक्षा (Low Earth Orbit-LEO) में सक्रिय मलबे को हटाने वाली तकनीकों का विकास किया जा रहा है।
- **ई. डिऑर्बिट (e-Deorbit):** यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा एक अन्य पहल ई. डिऑर्बिट (e-Deorbit) प्रारम्भ की गई है।
  - इसका उद्देश्य नेट और हार्पून (Net and Harpoon) का उपयोग करके गैर-कार्यात्मक उपग्रहों का संग्रहण एवं उन्हें पृथ्वी की कक्षा से बाहर करना है।
- **डेब्रिस एलिमिनेशन एंड रीएंट्री (DER):** अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) द्वारा डेब्रिस एलिमिनेशन एंड रीएंट्री (DER) पहल प्रारम्भ की गई है।
  - इसका उद्देश्य पृथ्वी की कक्षा से बाहर किए गए अंतरिक्ष मलबे के पुन: प्रवेश को रोकना तथा पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के विकास को कम करना है।
- **स्पेस डेब्रिस कैप्चर एक्सपेरिमेंट (Space Debris Capture Eñperiment):** जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) द्वारा स्पेस डेब्रिस कैप्चर एक्सपेरिमेंट नामक पहल को प्रारंभ किया गया है।

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024

जीएस मॉक टेस्ट-1

1. हाल ही में समाचारों में रहे संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(a) राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहेंगे।
(b) प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा ।
(c) किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
(d) राज्यपाल के पास क्षमादान, राहत आदि देने की शक्ति है।

2. राज्यपाल के कार्यालय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
2. किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किये जायेंगे।
3. मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नहीं।

उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं/हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

3. राज्य सभा या भारतीय संसद के उच्च सदन की भूमिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राज्यसभा जल्दबाजी में बनाए गए कानून पर नियंत्रण रखने के लिए एक पुनरीक्षण सदन के रूप में कार्य करती है।
2. राज्यसभा के पास अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं (AIS) बनाने की विशेष शक्ति है।
3. संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में, संविधान में संशोधन करने के संबंध में राज्यसभा के पास लोकसभा के समान शक्तियां हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: राज्यसभा में लंबित एक विधेयक, जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है।

कथन II: राज्य सभा संसद का एक स्थायी निकाय है जो विघटन के अधीन नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II कथन I की सही व्याख्या है।
(b) कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II कथन I की सही व्याख्या नहीं है।
(c) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(d) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

5. निम्नलिखित में से कौन सा समूह 'डिजिटल अधिकार' का प्रस्ताव देने वाला पहला समूह था?

(a) G20 (b) G7
(c) यूरोपीय संघ (d) BRICS

6. भारत के संविधान के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा 'विरोध करने के अधिकार' के संबंध में दिए गए अपवादों में शामिल नहीं है?

(a) भारत की संप्रभुता और अखंडता
(b) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
(c) वीआईपी आवाजाही
(d) मानहानि

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आखिरी राष्ट्रीय जनगणना जिसमें जाति संबंधी आंकड़े दर्ज और प्रकाशित किए गए थे, 1951 में हुई थी।
2. वर्तमान में, जनगणना केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए जाति संबंधित जानकारी दर्ज करती है।
3. भारत की जनगणना गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है।

उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं/हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. क्षमा से सजा और दोषसिद्धि दोनों समाप्त हो जाती है तथा अपराधी को सभी सजाओं, दंडों और अयोग्यताओं से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाता है।
2. लघुकरण का अर्थ है किसी विशेष तथ्य के कारण मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर कम सजा देना
3. परिहार का तात्पर्य सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: परिसीमन को 1976 में 25 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया था जिसे बाद में 2026 तक निलंबित कर दिया गया था।

कथन II: दक्षिण भारतीय राज्यों ने उत्तर की तुलना में कम प्रजनन दर और उच्च गर्भनिरोधक प्रसार के साथ जनसांख्यिकीय संक्रमण के अधिक उन्नत चरण का अनुभव किया।

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024

जीएस मॉक टेस्ट-2

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ब्रिटिश शासन की स्थापना के परिणामस्वरूप कृषकों तथा जनजातियों पर विभिन्न प्रकार के कर आरोपित किए गए।
2. कोलों ने 1831-32 में ब्रिटिश सरकार और बाहरी लोगों के खिलाफ विद्रोह कर दिया।
3. सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू दो भाई थे जिन्होंने 1855-1856 के सन्थाल विद्रोह का नेतृत्व किया था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

2. चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(1) बिहार के चंपारण जिले में किसानों को अपनी जमीन के कम-से-कम 3/20वें हिस्से पर नील उगाना होता था।
(2) बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर नील बेचने के लिये मजबूर किया जाता था।
(3) वर्ष 1917 में किसानों की स्थिति जानने तथा उनके सहयोग के लिए महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे।
(4) सरकार ने जून 1917 में एक जांच समिति नियुक्त की जिसमे सदस्य के रूप में गांधीजी को भी शामिल किया।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 4 (d) उपरोक्त सभी

3. बारदोली सत्याग्रह के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(1) यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गुजरात के बारदोली जिले में भू-राजस्व में वृद्धि करने के कारण किया गया था।
(2) वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों द्वारा राजस्व न देने का निर्णय किया गया।
(3) बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को 'सरदार' की उपाधि दी।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

4. संगम काल के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(1) संगम के सबसे पुराने तमिल व्याकरण ग्रंथ, तोलकाप्पियम के अनुसार, समाज तीन वर्गों अर्थात् अंतनार, अरासर, और वेलालर में विभाजित था।
(2) संगम ग्रंथों में मुल्लै (देहाती), मरुदम (कृषि), पालै (रेगिस्तान), नेथल (समुद्रवर्ती) और कुरिंचि (पहाड़ी) नामक भूमि के पांच मुख्य प्रकार पाए जाते हैं।
(3) संगम युग के दौरान महिलाओं की अच्छी स्थिति थी तथा उन्हें बौद्धिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति थी।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई नहीं

5. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से कथन सही नही है:

(1) ब्रिटिश भारत में जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी नामक भू-राजस्व की तीन प्रणालियों को देश मे लागू किया गया।
(2) जमींदारी प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में की।
(3) रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिचौलियों के माध्यम से 'रैयत' से राजस्व का संग्रह किया जाता था।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

6. निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

	युद्ध कला		**राज्य**
1.	ह्यूएन लैंगलॉन	:	मणिपुर
2.	सिलंबम	:	तमिलनाडु
3.	मुष्टि युद्ध	:	उत्तर प्रदेश
4.	काठी सामू	:	ओडिशा

ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) कोई नहीं

7. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे मे अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से क्या सत्य है:

1. इसका गठन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल, बॉम्बे में किया गया।
2. ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

8. राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन/कथनों की पहचान कीजिए:

1. राष्ट्रीय आंदोलन का पहला या आरंभिक चरण नरमदल का चरण (1885-1905) कहलाता है।
2. नरमपंथी नेताओं को ब्रिटिश सरकार में पूर्ण विश्वास था और उन्होंने पीपीपी मार्ग यानि विरोध, प्रार्थना और याचिका, को अपनाया था।
3. काम के नरमपंथी तरीकों से मोहभंग होने के कारण, 1892 के बाद कांग्रेस में गरमदल का प्रभाव बढ़ने लगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था

प्रमुख संकेतक

स्वास्थ्य एवं पोषण

बच्चों में पोषण की स्थिति

महत्वपूर्ण तथ्य

- ✓ **स्तनपान**
  - 6 महीने से कम उम्र के बच्चे जिन्हें केवल स्तनपान कराया जाता है : 63.7 प्रतिशत (NFHS 5)
    - ✧ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) 54.9 प्रतिशत
- ✓ **बौनापन (Stunting)**
  - 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनका कद छोटा (stunted) है (उम्र के अनुपात में कम लंबाई): 35.5 प्रतिशत (NFHS-5)
    - ✧ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) 38.4 प्रतिशत
- ✓ **दुर्बलता (Wasting)**
  - 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो वेस्टेड (wasted) हैं (ऊंचाई के अनुपात में कम वजन) : 19.3 प्रतिशत (NFHS-5)
    - ✧ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) 21.0 प्रतिशत
- ✓ **अल्प वजन**
  - 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन कम है (आयु के अनुपात में कम वजन) : 32.1 प्रतिशत (NFHS-5)
    - ✧ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) 35.8 प्रतिशत
- ✓ **अधिक वजन**
  - 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन अधिक है (ऊंचाई के अनुपात में कम वजन): 3.4 प्रतिशत (NFHS-5)
    - ✧ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) 2.1 प्रतिशत

प्रमुख पहलें

- ➢ **एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम** (Integrated Child Development Services Programme) का उद्देश्य छोटे बच्चों एवं माताओं को भोजन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण सेवाएं प्रदान करना है।
- ➢ भारत सरकार ने 2018 में **पोषण अभियान** शुरू किया था। इसका मकसद बच्चों पर शुरुआती 1,000 दिनों के दौरान अधिक ध्यान देना था।
- ➢ आयुष मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) के विभिन्न हस्तक्षेपों के तहत लगभग 4.37 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों ने **पोषण वाटिका** की स्थापना की है।
- ➢ **पोषण अभियान** के अंतर्गत हर साल सितंबर के महीने में राष्ट्रीय **पोषण माह** मनाया जाता है।
- ➢ इसमें प्रसवपूर्व देखभाल, इष्टतम स्तनपान, एनीमिया, विकास निगरानी, लड़कियों की शिक्षा, आहार, शादी की सही उम्र, स्वच्छता और स्वस्थ भोजन (खाद्य पोषण) पर केंद्रित एक महीने की गतिविधियां शामिल है।

प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए संपर्क का पहला बिंदु है। कुछ प्राथमिक देखभाल प्रदाता अस्पताल में भर्ती मरीजों की देखभाल भी कर सकते हैं।

- ➢ माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल उन रोगियों को सेवाएं प्रदान करती हैं जिनके लिए आम तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से अधिक कुशल चिकित्सा हेतु रेफर किया गया होता हैं। उदाहरण: जिला अस्पताल और ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।
- ➢ तृतीयक देखभाल चिकित्सा सेवाएं विशेष अस्पतालों या क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा प्रदान की जाती हैं जो विशेषज्ञ, उच्च निदान और उपचार सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं। उदाहरण: मेडिकल कॉलेज और उन्नत चिकित्सा अनुसंधान संस्थान।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ➢ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22 के अनुसार मार्च 2022 तक विभिन्न संकेतकों पर इनसे संबंधित डेटा निम्नलिखित हैं:
  - **उपकेंद्र (एससी)** : 157.9 हजार
  - **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)** : 24.9 हजार
  - **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)** : 5.5 हजार
  - **पीएचसी पर डॉक्टर** : 30.6 हजार
  - **डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात** - 1:834

सरकार की पहलें

- ➢ **आयुष्मान भारत योजना 2018** में शुरू की गई थी। यह सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है।
- ➢ **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना** सस्ती और विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताओं में सुधार के लिए 2003 में इस योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत नए एम्स की स्थापना की जाएगी और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का अपग्रेडेशन किया जाएगा।

राज्य परिदृश्य

इसके अंतर्गत हमने विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू की गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों, राज्य स्तर पर आयोजित बैठक एवं सम्मेलनों, सरकारों द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट्स तथा अन्य प्रमुख घटनाक्रमों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है, जिनसे सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

उत्तर प्रदेश

अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना

17 अप्रैल, 2024 को राम नवमी के अवसर पर सूर्य तिलक परियोजना के अंतर्गत अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मंदिर में तीन मिनट लंबा सूर्य तिलक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें श्री राम लला के मस्तक पर सूर्य की रोशनी की किरण डाली गई।

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) बेंगलुरु ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दर्पणों और 2 लेंसों वाला यह डिजाइन सूर्य तिलक के लिए निष्पादित किया गया था।

उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को GI टैग

अप्रैल 2024 में राज्य के 6 नए उत्पादों को GI टैग प्राप्त होने के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक जीआई-टैग उत्पाद वाले राज्य के रूप में अपना शीर्ष स्थान (75 उत्पादों) बरकरार रखा है।

- इन 6 नये उत्पादों में तिरंगी बर्फी एवं मेटल कास्टिंग क्राफ्ट (वाराणसी), थारू कढ़ाई (लखीमपुर खीरी), बेंत और बांस शिल्प एवं जरदोजी शिल्प (बरेली) तथा हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, पिलखुवा (हापुड़) शामिल है।

वाराणसी में 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक

28 मार्च, 2024 को वाराणसी में स्थित 'अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र' [ISARC] में '7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक' आयोजित की गई।

- बैठक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी शामिल हुए।
- वाराणसी में स्थित IRRI एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1960 में फिलीपीन सरकार के समर्थन से फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा की गई थी।

बिहार

जलवायु-लचीली कृषि कार्यान्वयन के लिए परियोजना

राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (RPCAU) ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलवायु-लचीली कृषि के कार्यान्वयन पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है।

- "बिहार सरकार के आवश्यक सहयोग से, विश्वविद्यालय 11 जिलों के 14 कृषि विज्ञान केंद्रों में नवीनतम तकनीकों और उन्नत बीजों पर शोध कर रहा है, जो बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं।
- इस परियोजना के माध्यम से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, मधुबनी, बेगुसराय और सीतामढ़ी जैसे जिलों में, किसानों की लागत और नुकसान को कम करते हुए फसल उत्पादकता को बढ़ाना एक प्रमुख लक्ष्य है।

बिहार में एशियाई जलपक्षी जनगणना (AWC)

हाल ही में बिहार के गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर जिलों में एशियाई जलपक्षी जनगणना (AWC) आयोजित की गई।

- यह जनगणना दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा की गई।
- AWC एशियाई क्षेत्र में वॉटरबर्ड की आबादी की निगरानी के लिए वेटलैंड इंटरनेशनल और एशियन वेटलैंड ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है।

मध्य प्रदेश

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) को लागू करने में अग्रणी

मध्य प्रदेश, केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) को लागू करने में अग्रणी है, राज्य ने अब तक वृक्षारोपण/हरियाली अभ्यास के लिए सबसे अधिक 954 हेक्टेयर स्वीकृत निम्नीकृत वन भूमि स्वीकृत की है।

- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के तहत पिछले दो माह में वृक्षारोपण के लिए 10 राज्यों में 4,980 हेक्टेयर में विस्तृत 500 से अधिक भूमि पार्सल को मंजूरी दी गई है।
- मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना (845 हेक्टेयर), छत्तीसगढ़ (713 हेक्टेयर), गुजरात (595 हेक्टेयर) और असम (454 हेक्टेयर) का स्थान है।

गुजरात

खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क

अदाणी समूह ने गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित किया है, जिसमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए 45 गीगावॉट की विशाल क्षमता है।

न्यूज़ बुलेट्स

न्यूज बुलेट्स के इस खंड में हम उन समसामयिक घटनाक्रमों को प्रस्तुत करते हैं, जिनके लिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि परीक्षा की तैयारी के लिए इन्हें संक्षिप्त रूप में पढ़ना पर्याप्त होता है। ऐसे घटनाक्रमों को हम पत्रिका के शुरुआती नियमित स्तंभों में शामिल करने के बजाय पृथक रूप से इस खंड के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं।

राष्ट्रीय संक्षिप्तिकी

एथिकल लीडरशिप

- हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा 'भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), बोधगया' के छठे दीक्षांत समारोह के दौरान अपने संबोधन भाषण में 'नैतिक नेतृत्व' (Ethical Leadership) के महत्त्व पर चर्चा की।
- 'एथिकल लीडरशिप' की अवधारणा नेतृत्व की एक विशिष्ट शैली को संदर्भित करती है; जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों एवं नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता को महत्व दिया जाता है।
- इसके तहत नेता अपने निर्णय लेने एवं कार्यों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा निष्पक्षता को प्राथमिकता देते हैं, जिससे उनकी टीम या संगठन के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित होते हैं।

दो दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सागर कवच'

- 1-2 अप्रैल, 2024 के मध्य भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सागर कवच 01/24' आयोजित किया गया।
- अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शामिल हुईं।
- इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र के खतरे से निपटने के दौरान तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता और सुदृढ़ स्थिति का आकलन करना है।
- इस अभ्यास में समुद्री क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए तटरक्षक बल और अन्य तटीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ भारतीय नौसेना के जहाजों को तैनात किया गया।

समलैंगिक समुदाय के कल्याण हेतु समिति का गठन

- हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप समलैंगिक समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जाँच के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति को गठित करने हेतु अधिसूचना जारी की गई है।
- इसके अन्य सदस्यों में गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार विकास मंत्रालय के सचिव शामिल हैं।
- यह समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाएगी कि समलैंगिक समुदाय को वस्तुओं और सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुँच में किसी भी तरह के भेदभाव का सामना न करना पड़े या उन्हें किसी भी तरह की हिंसा का खतरा न हो।

वन, एक राष्ट्रीय संपत्ति है: उच्चतम न्यायालय

- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में इस बात पर जोर दिया कि वन एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति हैं और देश की वित्तीय संपदा में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं।
- वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम (FCAA) 2023 पर चिंताओं के बीच, एक निजी व्यक्ति को वन भूमि उपहार में देने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ तेलंगाना राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी।
- अदालत ने निजी व्यक्तियों को वन भूमि देने के कृत्य की निंदा की और विरोधाभासी जानकारी प्रदान करने के लिए वन अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया।

पाठ्यपुस्तकों पर कॉपीराइट का दावा

- हाल ही में, आंध्र उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार गणित और विज्ञान से जुड़ी पाठ्यपुस्तकों पर कॉपीराइट का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी सामग्री को साहित्यिक नहीं माना जाता है।
- कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत, पुस्तकों को मौलिक साहित्यिक कृति माना जाता है और उन्हें कानूनी संरक्षण दिया जाता है। कॉपीराइट का तात्पर्य साहित्यिक, नाटक, संगीत, फिल्म और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों और निर्माताओं को प्रदान किया गया कानूनी अधिकार है।

लघु संचिका

प्रायः सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में नियुक्ति, निधन, पुरस्कारों, चर्चित पुस्तकों, दिवसों आदि से काफी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए संक्षिप्त स्वरूप में समसामयिक घटनाक्रमों का कवरेज पर्याप्त होता है। इसे ध्यान में रखकर हम इस खंड में अति संक्षिप्त रूप में इन समसामयिक घटनाक्रमों का प्रस्तुतीकरण करते हैं।

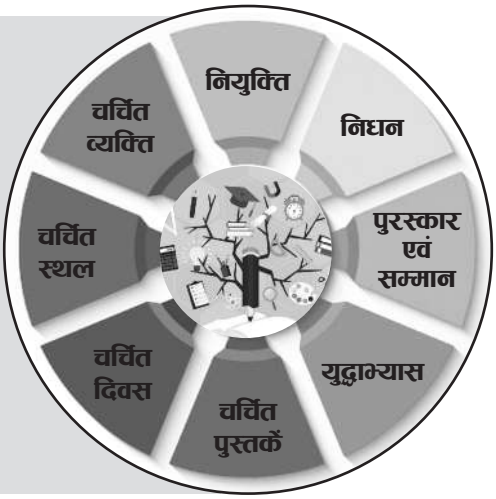

चर्चित व्यक्ति/ नियुक्ति

एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी

30 अप्रैल, 2024 को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें 'नौसेना प्रमुख' (Chief of the Naval Staff) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

- इससे पूर्व वे नौसेना के उप-प्रमुख थे। उन्होंने एडमिरल आर. हरि कुमार का स्थान लिया।
- एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जुलाई 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे।

नलिन प्रभात

हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को देश के आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

- प्रभात आंध्र प्रदेश काडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं।
- कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 31 अगस्त, 2028 यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की अवधि के लिए एनएसजी के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

नरसिंह यादव

24 अप्रैल, 2024 को राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया।

- एथलीट आयोग का गठन पहलवानों की शिकायतों के निपटान के लिए किया गया है।
- WFI भारत में कुश्ती का शासी निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

जगजीत पवाड़िया

भारत की उम्मीदवार जगजीत पवाड़िया को वर्ष 2025-2030 की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) के लिए फिर से चुना गया है।

- इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण अभिसमयों के कार्यान्वयन हेतु एक स्वतंत्र एवं अर्द्ध-न्यायिक निगरानी निकाय है।
- इसकी स्थापना सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, 1961 के तहत वर्ष 1968 में की गई थी।

मनोज पांडा

केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (Institute of Economic Growth) के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है।

- 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए 31 अक्टूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा।
- 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति मुर्मु द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था।

निधन

पीटर हिग्स

8 अप्रैल, 2024 को नोबेल पुरस्कार विजेता, ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

- पीटर हिग्स का जन्म 29 मई, 1929 को ब्रिटेन के न्यूकैसल अपॉन टाइन में हुआ था।
- पीटर हिग्स, 'हिग्स-बोसोन पार्टिकल' या 'गॉड पार्टिकल' की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, इन्होंने 1964 में हिग्स बोसोन की भविष्यवाणी की थी। हिग्स बोसोन इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, फोटॉन या न्यूट्रिनो जैसा एक प्राथमिक कण है।
- हिग्स ने फ्रेंकोइस एंगलर्ट के साथ अपने कार्य के लिए वर्ष 2013 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था।

सुधीर कक्कड़

22 अप्रैल, 2024 को 'भारतीय मनोविज्ञान के जनक' के रूप में प्रसिद्ध सुधीर कक्कड़ का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

- सुधीर कक्कड़ का जन्म वर्ष 1938 में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हुआ था।
- इन्होंने भारत में मनोविश्लेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, मानव व्यवहार और संस्कृति की जटिलताओं की खोज की।

खेल परिदृश्य

खेल जगत में हाल के घटनाक्रमों पर आधारित

खेल व्यक्तित्व

युवराज सिंह

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा क्रिकेटर युवराज सिंह को आगामी ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत के क्रिकेटर युवराज सिंह ने पुरुष T20 विश्व कप 2007 के दौरान एक ओवर में छह छक्के लगाए थे।

- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के शुरू होने में केवल 36 दिन शेष हैं, इसलिए उन्हें 36 दिनों के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
- T20 विश्व कप जून 2024 में वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाएगा।

दीपिका सोरेंग

हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फारवर्ड खिलाड़ी दीपिका सोरेंग को वर्ष के उदीयमान खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया।

- हॉकी इंडिया द्वारा उन्हें 31 मार्च, 2024 को आयोजित छठे वार्षिक पुरस्कार 2023 के दौरान इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- दीपिका सोरेंग ने वर्ष 2023 में महिला जूनियर एशिया कप में भारत के लिए पदार्पण किया।

डी. गुकेश

21 अप्रैल, 2024 को भारतीय ग्रैंडमास्टर डी. गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा के खिलाफ महत्वपूर्ण ड्रॉ खेलकर 14 में से 9 अंक हासिल कर विश्व शतरंज का यह खिताब जीत लिया।

- 17 वर्षीय ग्रैंडमास्टर डी. गुकेश यह खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चौलेंजर बन गए हैं। इन्होने 40 वर्ष पूर्व महान गैरी कास्परोव द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

टेनिस

मियामी ओपन 2024 टेनिस

भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एब्डेन ने फ्लोरिडा के हार्ड रॉक स्टेडियम में मियामी ओपन 2024 टेनिस पुरुष युगल खिताब जीता।

- शीर्ष वरीयता प्राप्त बोपन्ना और एब्डेन की जोड़ी ने दूसरी वरीयता प्राप्त अमेरिकी ऑस्टिन क्राजिसेक और क्रोएशिया के इवान डोडिग के खिलाफ जीत हासिल की।
- लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के बाद बोपन्ना मियामी ओपन खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं।

बीएमडब्ल्यू ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट

21 अप्रैल, 2024 को भारत के युकी भांबरी और फ्रांसीसी साथी अल्बानो ओलिवेटी ने जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब (doubles title) जीता।

- बीएमडब्ल्यू ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन 15 अप्रैल 2024 से 21 अप्रैल 2024 के मध्य हुआ।
- युकी भांबरी बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं।

तीरंदाजी

तीरंदाजी विश्वकप 2024 स्टेज–1

28 अप्रैल, 2024 को तरुणदीप राय, प्रवीण जाधव और धीरज बोम्मदेवरा की भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2024 स्टेज–1 (2024 Archery World Cup Stage 1) में स्वर्ण पदक जीता। जबकि दीपिका कुमारी ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में रजत पदक जीता।

- यह 14 वर्षों में पुरुषों की रिकर्व टीम तीरंदाजी में भारत का पहला विश्व कप स्वर्ण पदक था।
- 23 से 28 अप्रैल, 2024 के मध्य चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण–1 का आयोजन किया गया।
- इस प्रतियोगिता में भारत ने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक अर्जित किए।

खेल पुरस्कार

25वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स

22 अप्रैल, 2024 को 25वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स स्पेन की राजधानी मैड्रिड के पलासियो डी सिबेलेस में आयोजित हुआ।

- टेनिस के महान खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djvokovic) ने पांचवी बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवॉर्ड जीता।
- स्पेन की विश्व कप विजेता फुटबॉल स्टार ऐताना बोनमती ने वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता।
- ऐटाना बोनमती लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली फुटबॉलर है। ■■

परीक्षा सार

झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रा. परीक्षा-2023

व्याख्या सहित हल प्रश्न-पत्र

1. निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित है?

नोबल पुरस्कार प्राप्तकर्ता (2022)		पुरस्कार का क्षेत्र
(a) स्वांते पाबो	–	भौतिक विज्ञान
(b) एलेन आस्पेक्ट	–	रसायन विज्ञान
(c) मोर्टन मेल्डल	–	आर्थिक विज्ञान
(d) एनी एर्नाक्स	–	साहित्य

2. निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल, 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ था?

(a) दिल्ली (b) काठमांडू
(c) कुआला लंपुर (d) जकार्ता

3. निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा, 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान 'द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार' से सम्मानित किया गया था?

(a) मिश्र (b) मलेशिया
(c) इंडोनेशिया (d) सूरीनाम

4. The Coalition Years पुस्तक के लेखक कौन हैं?

(a) शशि थरूर (b) प्रणब मुखर्जी
(c) रवि माथुर (d) एम.एम. सिंह

5. 'उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन' (NATO) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

I. इस संगठन में 42 राष्ट्र सदस्य हैं।
II. इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल I (b) केवल II
(c) I तथा II दोनों (d) न तो I और न ही II

6. G20 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

I. 1 दिसम्बर, 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी।
II. G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में सम्पन्न हुआ था।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल I (b) केवल II
(c) I एवं II दोनों (d) न तो I और न ही II

7. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद, समान नागरिक संहिता (UCC) की बात करता है?

(a) अनुच्छेद 43 (b) अनुच्छेद 44
(c) अनुच्छेद 45 (d) अनुच्छेद 46

8. 2023 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी?

(a) लॉस एंजेलिस (b) बॉस्टन
(c) जर्सी (d) न्यूयॉर्क

9. निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित है?

पद्मश्री प्राप्तकर्ता		पुरस्कार का क्षेत्र
(a) श्री आनन्द कुमार	–	विज्ञान व अभियांत्रिकी
(b) श्री मूलचन्द लोढा	–	साहित्य तथा शिक्षा
(c) श्री जानुम सिंह सोय	–	सार्वजनिक मामले
(d) श्री पी. कल्याणसुंदरम	–	सामाजिक कार्य

10. निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है?

(a) कर्नाटक (b) मध्य प्रदेश
(c) राजस्थान (d) दिल्ली

11. निम्न में से कौन, भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि थे?

(a) अफगानिस्तान के राष्ट्रपति
(b) मिश्र के राष्ट्रपति
(c) संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति
(d) इंडोनेशिया के राष्ट्रपति

12. सुडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का नाम था।

(a) ऑपरेशन देवी शक्ति (b) ऑपरेशन गंगा
(c) ऑपरेशन आदिस अबाबा (d) ऑपरेशन कावेरी

13. भारतीय संसद के नये भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था?

(a) रवि मोदी (b) बिमल रॉय
(c) बिमल पटेल (d) डी. राधाकृष्णन

14. निम्नांकित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) के बारे में कौन-सा कथन सही है/हैं?

I. भारत CDRI का सदस्य है।
II. यह एक UN एजेंसी है।
III. इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है।
IV. इसकी शुरुआत G20 समिट, 2023 में हुई।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल I (b) केवल I और II
(c) केवल I, III और IV (d) I, II, III तथा IV

पत्रिका सार

इस खंड में हम भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2024 में प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं की परीक्षोपयोगी तथ्यों का संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अभ्यर्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

योजना (अप्रैल 2024)

भू-वैज्ञानिक पारिस्थितिक-तंत्र

- भारत विश्व का **7वां सबसे बड़ा देश** है और इसमें समृद्ध भौगोलिक विविधता है।
- हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शृंखला है, जो भारतीय भूभाग को तिब्बती पठार से अलग करती है। हिमालय में **माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा तथा नंगा पर्वत** के रूप में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं।
- दक्षिण से उत्तर जाने पर इसमें विभिन्न समांतर पर्वत शृंखलाएं देखने को मिलती हैं- **शिवालिक, लघु हिमालय या हिमाचल शृंखला, वृहत् हिमालय या हिमाद्रि तथा तिब्बत हिमालय**।
- उत्तरी मैदान को **'भारत का वृहत् मैदान'** भी कहा जाता है, यह विश्व के सर्वाधिक व्यापक जलोढ़ मैदानों में से एक है।
- हिमालय से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने वाली नदियां पहाड़ी क्षेत्र से उतरकर सघन और मोटे तलछट के अंश निक्षेपित करती है, जिन्हें **'भाबर'** के रूप में जाना जाता है। 'भाबर' के दक्षिण में **तराई बेल्ट** स्थित है।
- मैदानी क्षेत्र के पुराने जलोढ़ को **'भांगर'** के नाम से जाना जाता। यह क्षेत्र **चूनेदार पत्थर** एवं कंकड़ से ढका रहता है, जिसे **'कांकड़'** के नाम से जाना जाता है।
- **प्रायद्वीपीय पठार** भारतीय भूभाग की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है।
- यह पठार पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से लेकर पूर्व में छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है।
- इसमें मध्य भारत की महत्वपूर्ण पर्वत शृंखलाएं जैसे **विंध्य, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और सरगुजा** पर्वतमाला के साथ-साथ पश्चिमी और पूर्वी घाट शामिल हैं।
- **थार रेगिस्तान, एक विस्तृत शुष्क क्षेत्र** है, जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है।
- थार रेगिस्तान के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में स्थित दलदली क्षेत्र को **'कच्छ का महान रण'** कहा जाता है। कच्छ भारत के प्रमुख नमक उत्पादक जिलों में से एक है।
- **अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह** में लगभग 572 द्वीप शामिल हैं, जिनमें से केवल 37 द्वीप ही आबाद (बसे हुए) हैं।
- इन द्वीपों का निर्माण मुख्य रूप से ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। अंडमान सागर में **बैरेन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी** है।
- **लक्षद्वीप** के रूप में भारत के पश्चिमी तट पर एक अन्य द्वीप समूह स्थित है। इसमें लगभग 36 **द्वीप हैं**, जिन्हें मुख्य रूप से समुद्री वनस्पतियों और मूंगा द्वीपों के कारण अद्वितीय माना जाता है।

पश्चिमी घाट का एक समग्र अन्वेषण

- पश्चिमी घाट को **सह्याद्रि पर्वत शृंखला** के नाम से भी जाना जाता है। इसे **वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट** तथा **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** की मान्यता प्राप्त है।
- इसका विस्तार 8°-22° **उत्तरी अक्षांशों** के मध्य उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। यहां **गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा** जैसी दक्षिण भारत की अनेक महत्वपूर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं।
- इसके विस्तार क्षेत्र में 6 **राज्य** गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश (दादरा और नगर हवेली) **शामिल** हैं।
- पश्चिमी घाट को **तीन प्राथमिक भागों** में विभाजित किया जा सकता है:
  - **उत्तरी घाट:** गुजरात से महाराष्ट्र तक विस्तृत यह क्षेत्र पश्चिमी घाट का सर्वाधिक निचला क्षेत्र माना जाता है।
  - **केंद्रीय घाट:** इसका विस्तार कर्नाटक से केरल तक है।
  - **दक्षिणी घाट:** यह क्षेत्र केरल से तमिलनाडु तक विस्तृत है और पश्चिमी घाट के सबसे विच्छेदित खंड का प्रतिनिधित्व करता है।
- पश्चिमी घाट में **निम्नलिखित प्रकार के वन** पाए जाते हैं- (i) शुष्क झाड़ियां वनस्पति (ii) शुष्क पर्णपाती वन (iii) नम पर्णपाती वन (iv) अर्द्ध-सदाबहार वन (v) सदाबहार वन (vi) शोला; और (vii) उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदान।
- IUCN रेड लिस्ट के अनुसार पश्चिमी घाट में विश्व स्तर पर खतरे के रूप में सूचीबद्ध लगभग 325 **प्रजातियां** पाई जाती हैं।

चर्चित शब्दावली

विगत कुछ वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में चर्चित शब्दावलियों से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। परीक्षा की इसी मांग के अनुरूप समसामयिक सन्दर्भ में चर्चा में रही शब्दावलियों के विशेष अध्ययन की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखकर ही हम यह खंड प्रस्तुत कर रहे हैं।

डॉक्सिंग

हाल के दिनों में, दुनिया भर में इंटरनेट पर डॉक्सिंग (Doxxing) की घटनाएं बढ़ रही हैं।

- 'डॉक्सिंग' शब्द 'ड्रॉपिंग डॉक्स' से लिया गया है। यह ऑनलाइन उत्पीड़न का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित की जाती है।
- 1990 के दशक में ऑनलाइन हैकर समुदाय में उत्पन्न हुई डॉक्सिंग की शुरुआत हैकरों के बीच संघर्ष से हुई, जो प्रतिशोध या धमकी के रूप में प्रतिद्वंद्वियों की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करते थे।
- इस जानकारी में उनका पूरा नाम, घर का पता, टेलीफोन नंबर, कार्य का स्थान और अन्य संवेदनशील जानकारी शामिल हो सकती है।
- यह अक्सर किसी की छवि को उजागर करने, उसे धमकाने या भयभीत करने के लिए किया जाता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे शारीरिक नुकसान, पीछा करना या नौकरी छूट जाना।

मेन5सीवी

- हाल ही में, नाइजीरिया ने मेनिनजाइटिस के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, वह Men5CV नामक एक नया, अत्यधिक प्रभावी टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
- मेन5सीवी टीका मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के ए, सी, डब्ल्यू, वाई और एक्स स्ट्रेन से बचाता है, ये सभी मेनिनजाइटिस और रक्त विषाक्तता का कारण बन सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा इसकी अनुशंसा की गई है।

सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क

2 अप्रैल, 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'हल्दीराम' चिह्न (Mark) को खाद्य पदार्थों, रेस्तरां और भोजनालयों के लिए एक 'सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क' (Well-known Trademark) घोषित किया।

- 'हल्दीराम' चिह्न और लोगो का उपयोग खाद्य उद्योग में 1960 के दशक से किया जा रहा है और इसने एक सुप्रसिद्ध चिह्न का दर्जा हासिल कर लिया है।
- एक सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क जनता द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा किसी प्रमुख कंपनी या ब्रांड के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ा होता है।
- इन ट्रेडमार्कों को, जिन्हें अक्सर 'सुप्रसिद्ध' ट्रेडमार्क (TM) कहा जाता है, नियमित पंजीकृत ट्रेडमार्कों की तुलना में ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत अधिक सुरक्षा प्राप्त होती है।
- जबकि एक नियमित पंजीकृत ट्रेडमार्क केवल उसके विशिष्ट वर्ग की वस्तुओं या सेवाओं के अंतर्गत ही सुरक्षित होता है तथा उसके पंजीकरण के भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होता है, प्रसिद्ध ट्रेडमार्क को सभी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं तथा भौगोलिक स्थानों में व्यापक सुरक्षा प्राप्त होती है।

पीस क्लॉज

हाल ही में, भारत ने अपने किसानों को दिए जाने वाले चावल के लिए निर्धारित सब्सिडी सीमा का उल्लंघन करने के कारण विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शांति खंड (Peace Clause) लागू किया।

- पीस क्लॉज डब्ल्यूटीओ सदस्यों को डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान मंच पर विकासशील देशों के लिए निर्धारित सब्सिडी सीमा में किसी भी उल्लंघन को चुनौती देने से बचने की सुविधा प्रदान करता है।
- 2013 में बाली मंत्रिस्तरीय बैठक में स्थापित, शांति खंड को डब्ल्यूटीओ सदस्यों के साथ एक स्थायी समाधान पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध अंतरिम उपाय के रूप में पेश किया गया था।
- 1986-88 के संदर्भ मूल्य के आधार पर, खाद्य उत्पादन के मूल्य की 10% सीमा से अधिक सब्सिडी को व्यापार-विकृत करने वाला माना जाता है, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए।

जीपीएस स्पूफिंग

जीपीएस स्पूफिंग (GPS Spoofing), उपग्रहों को गलत स्थान संकेत भेजने की एक प्रथा है, जो अमेरिका द्वारा संचालित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को प्रभावित कर रही है, जिससे विमानों, लोगों और जहाजों की स्थिति उनके वास्तविक स्थानों से सैकड़ों मील दूर प्रदर्शित होती है।

- शोधकर्ता इस घटना का श्रेय इजरायल को देते हैं, जिसका उद्देश्य रॉकेटों और मिसाइलों को रोकना है, लेकिन इससे विमानन सुरक्षा और नेविगेशन प्रणालियों के लिए खतरा पैदा हो रहा है।
- जीपीएस स्पूफिंग वास्तविक संकेतों को गलत संकेतों से कवर कर देती है, जिससे स्वचालित सुरक्षा प्रणालियां बाधित हो जाती हैं और पायलटों तथा जहाज कप्तानों को जीपीएस आधारित नेविगेशन छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ■■

संसद प्रश्नोत्तारी

प्रारंभिक परीक्षा तथ्य: वनलाइनर रूप में

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-2020 तक की अवधि में भारत की औसत वार्षिक ऊर्जा तीव्रता सुधार दर लगभग कितनी रही है? - **2.4 प्रतिशत**
- ऊर्जा संरक्षण हेतु बड़े ऊर्जा गहन क्षेत्रों के संबंध में सरकार द्वारा कौनसी प्रमुख पहल क्रियान्वित की जा रही है? - **निष्पादन, प्राप्ति एवं व्यापार (PAT)**
- किस पहल के तहत प्रमुख ऊर्जा खपत वाले उपकरणों को ऊर्जा दक्षता के आधार पर 1 से 5 स्टार तक रेटिंग दी जाती है? - **मानक तथा लेबलिंग स्कीम**

पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन

- पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधियों के लिए आयोजित 'पंचायत से संसद तक कार्यक्रम' का उद्घाटन किसने किया? - **लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला**
- पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था? - **संवैधानिक संसदीय अध्ययन संस्थान (ICPS)**

राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, 2024

- राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, 2024 की थीम क्या है? - **युवाओं की आवाज: राष्ट्र परिवर्तन के लिए सहभागी और सशक्त बने**
- राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? -**9 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 (नई दिल्ली)**
- राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? -**युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय**

ड्राई फ्रूट्स और नट्स की प्रदर्शनी और ट्रेड कॉन्फ्रेंस 'मेवा इंडिया' 2024

- 16 फरवरी, 2024 को ड्राई फ्रूट्स और नट्स की प्रदर्शनी और ट्रेड कॉन्फ्रेंस "मेवा इंडिया 2024" का उद्घाटन कहां किया गया? - **नई दिल्ली (यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर)**
- ACRAW ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स काउंसिल द्वारा आयोजित 'मेवा इंडिया' 2024 का उद्घाटन किसने किया? - **लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला**

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना

- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PM-JAY) के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी राशि स्वास्थ्य कवर के लिये प्रदान की जाती है? -**5 लाख रुपये**
- ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किये गए किस फ्रेमवर्क के तहत स्वास्थ्य परिचर्या लाभ प्रदान किये जाते है? -**स्माइल:आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता**
- देश में गुणवतायुक्त मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? - **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NTMHP)**

अभिनव और टिकाऊ निर्माण प्रौद्योगिकी

- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) के तहत, आवासों के तीव्र लागत प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री एवं पर्यावरण अनुकूल और आपदा-रोधी प्रोद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की स्थापना की गई है? - **प्रौद्योगिकी उप-मिशन (TSM)**
- ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया का लक्ष्य है? -**विश्व स्तर के सर्वोतम उपलब्ध सिद्ध निर्माण प्रौद्योगिकी की पहचान करना**
- ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया के अंतर्गत विश्व भर की कितनी नवीन सिद्ध निर्माण प्रोद्योगिकियों को सूचीबद्ध किया गया है? - **54**

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

- राष्ट्रीय आरोग्य निधि (Rashtriya Arogya Nidhi) का गठन एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में किस वर्ष में किया गया? -**1997 में**
- राष्ट्रीय आरोग्य निधि का उद्देश्य क्या है? -**केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने वाले गरीब मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना**

इफको नैनो यूरिया के लिए गाइडलाइन्स

- 6 मार्च, 2023 की अधिसूचना के अनुसार नैनो साइंस एंड रिसर्च सेंटर द्वारा निर्मित किये जाने वाले नैनो यूरिया को कितने वर्षों के लिए अधिसूचित किया गया है? -**3 वर्षों के लिए**
- इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) द्वारा कलोल, फूलपुर और आवंला में 17 करोड़ बोतलों (प्रति वर्ष) की क्षमता वाले कितने नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किये गए है? -**3 नैनो यूरिया संयंत्र**
- उर्वरक कंपनियों की अधिसूचना के अनुसार भारत में कितने नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किये जाने है? -**6 नैनो यूरिया संयंत्र**

'पार्लियामेंट आर्ट' कॉफी टेबल बुक का विमोचन

- 6 मार्च, 2024 को संसद भवन में अद्वितीय कला और मूर्तिकला का परिचय देने वाली कॉफी टेबल बुक " पार्लियामेंट आर्ट" का विमोचन किसने किया? - **लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला**
- कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में किस संस्था द्वारा किया गया? - **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र**

फैक्ट शीट

इस खंड के तहत हम उन विषय-वस्तुओं को कवर करते हैं, जो प्रतियोगीता परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं तथा जिनसे परीक्षाओं में बार-बार तथ्य एवं आंकड़े संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं।

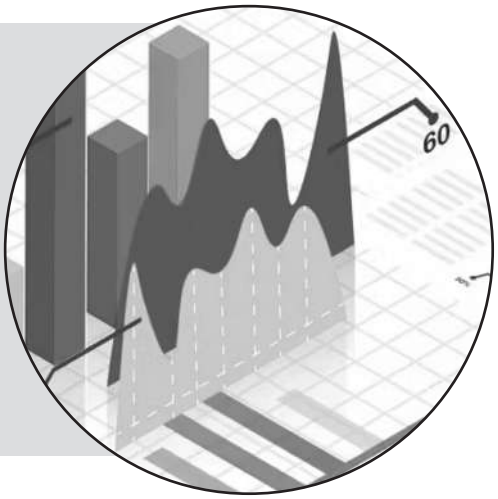

भारत में लॉजिस्टिक्स सेक्टर

वर्तमान परिदृश्य

- **मूल्य:** 2021 में भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का मूल्य 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2025 तक सीएजीआर 10-12% बढ़कर 380 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होने की उम्मीद है।
- **वेयरहाउसिंग स्टॉक:** शीर्ष 8 टियर-1 शहरों में ग्रेड ए और बी वेयरहाउसिंग स्टॉक की मांग 287 मिलियन वर्ग फुट (2021) से बढ़कर 500 मिलियन वर्ग फुट (2025) हो जाएगी।
- **कोल्ड स्टोरेज:** कोल्ड स्टोरेज का स्टॉक बढ़कर 41 मिलियन वर्ग फुट (2023) होने की उम्मीद है।
- **लॉजिस्टिक लागत को कम करना:** सरकार का लक्ष्य 2030 तक लॉजिस्टिक की लागत को कम करके सकल घरेलू उत्पाद के 8-9% तक करना है।

लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला में बुनियादी ढांचा निवेश

- ✓ **भारतमाला परियोजना**
- कार्यक्रम के तहत दो चरणों में लगभग 65,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाना है, जिसकी अनुमानित लागत ~USD 84 बिलियन है।
- ✓ **मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP)**
- सरकार ने ~USD 6.2 Bn के निवेश परिव्यय के साथ 35 MMLP की योजना बनाई है।
- ✓ **सागरमाला और अंतर्देशीय जलमार्ग**
- इसका उद्देश्य भारत की 7,500 किमी लंबी तटरेखा और 14,500 किमी संभावित नौगम्य जलमार्गों का उपयोग करके देश में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है।
- 2015-35 के बीच कार्यान्वयन के लिए 67 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की 800+ परियोजनाओं की पहचान की गई है।

हालिया नीति और विनियामक परिवर्तन

- ✓ **लॉजिस्टिक्स को बुनियादी ढांचे का दर्जा**
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को आसान शर्तों पर बुनियादी ऋण (Infra-Lending) उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगा।

भारत में फार्मा सेक्टर

वैश्विक स्तर पर भारत, जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़े निर्माता के रूप में विख्यात है। इसका फार्मास्युटिकल उद्योग सस्ती जेनेरिक दवाएं प्रदान कर वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत की स्थिति

- **वैश्विक वैक्सीन उत्पादन** में भारत की हिस्सेदारी 60% है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक बनाती है।
- भारत वैश्विक स्तर पर **जेनेरिक दवाओं** का सबसे बड़ा प्रदाता है, जो मात्रा के हिसाब से वैश्विक आपूर्ति में **20% हिस्सेदारी** रखता है।

निर्यात

- **फार्मास्युटिकल्स निर्यात** का वर्तमान मूल्य USD 50 बिलियन का है जिसमें 200 से अधिक देशों में भारतीय फार्मा कंपनियों का निर्यात होता है।
- इसके वर्ष 2024 तक 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा वर्ष 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

योजनाएं एवं पहलें

- भारत सरकार द्वारा **बल्क ड्रग पार्कों** की स्थापना को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं।
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने MSME की रणनीतिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए **'फार्मास्युटिकल उद्योग को सुदृढ़ बनाने'** (SPI) के लिये योजनाएं शुरू की हैं।
  - यह योजना फार्मास्युटिकल क्षेत्र में MSME इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये क्रेडिट लिंक्ड पूंजी और ब्याज सब्सिडी के साथ-साथ रिसर्च सेंटर, टेस्टिंग लैब आदि के लिये 20 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान करती है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंजूरी दी है।
- फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना फार्मास्युटिकल क्षेत्र में MSME को उन्नत तकनीक की सुविधा प्रदान करेगा।
  - इसमें तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के साथ अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 10% की पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान है। ■■

समसामयिक प्रश्न

अप्रैल 2024 के घटनाक्रम पर आधाारित

1. सूर्य तिलक परियोजना के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस परियोजना के अंतर्गत श्री राम मंदिर, अयोध्या में सूर्य तिलक समारोह आयोजित किया गया।
2. भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3. 4 दर्पणों और 2 लेंसों वाला यह डिजाइन सूर्य तिलक के लिए निष्पादित किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मध्य प्रदेश, केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) को लागू करने में अग्रणी है।
2. इस प्रोग्राम के तहत पिछले दो माह में वृक्षारोपण के लिए 10 राज्यों में भूमि पार्सल को मंजूरी दी गई है।
3. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक बाजार-आधारित पहल है, यह स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करती है।
4. 13 अक्टूबर, 2023 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने इस कार्यक्रम की घोषणा की थी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) कथन 1 और 3 (b) कथन 2 और 4
(c) कथन 1, 2 और 3 (d) कथन 1, 2, 3 और 4

3. समलैंगिक समुदाय के मुद्दों के समाधान हेतु गठित समिति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस समुदाय से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए 6 सदस्यीय समिति के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की गई।
2. इस समिति की अध्यक्षता विधि एवं न्याय मंत्रालय के कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी।
3. समिति यह सुनिश्चित करने के उपायों पर गौर करेगी कि समलैंगिक लोगों को ऐच्छिक चिकित्सा उपचार और सर्जरी का सामना न करना पड़े।

उपरोक्त कथनों के आधार पर असत्य विकल्प का चयन करें-

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

4. हाल ही में, विभिन्न राज्यों को दिए गए GI टैग के संदर्भ में, कौन-सा युग्म असुमेलित है?

(a) जापी असम
(b) तिरंगी बर्फी उत्तर प्रदेश
(c) माताबारी पेड़ा त्रिपुरा
(d) थारू कढ़ाई मध्य प्रदेश

5. एक्सोस्केलेटन पर पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कथन (a)- बेंगलुरु में 'एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों' पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया।
2. कारण (R)- एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी में पहनने योग्य संरचनाएं शामिल हैं जो मानव शरीर की क्षमताओं को बढ़ाती हैं।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(b) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(d) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

6. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों पर दिए गए निर्णय के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सुरक्षित स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 इस अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर असत्य विकल्प का चयन करें-

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

7. हाल ही में चर्चा में रही, शोम्पेन जनजाति किस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में निवास करती है?

(a) लक्षद्वीप (b) नगालैंड
(c) अंडमान एवं निकोबार (d) हिमाचल प्रदेश

8. हाल ही में, चर्चा में रहें 'सितवे' बंदरगाह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत को अपने पहले विदेशी बंदरगाह 'सितवे' को संचालित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है।
2. सितवे बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से माल के लिए एक आवश्यक आउटलेट के रूप में कार्य करता है।
3. यह कालादान नदी के मुहाने पर स्थित है, जो दक्षिणी चीन सागर में गिरती है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें-

करेंट अफेयर्स वनलाइनर

सरकारी समाचार सेवाओं-PIB, AIR इत्यादि से संकलित

राष्ट्रीय

- हाल ही में किस आयोग ने अपने नए लोगो और आदर्श वाक्य, "यत्र इतिहासम् भविष्यायाम् संरक्षित:" का अनावरण किया? **- भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग**
- भारतीय वायु सेना (IAF) ने हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया? **- डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म**
- 23 अप्रैल, 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने 'भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी' (Climate Clock) कहां स्थापित की है? **- CSIR मुख्यालय, नई दिल्ली**
- 22 अप्रैल, 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? **- IIT दिल्ली**
- भारतीय नौसेना ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी समुद्र-तट पर किस अभ्यास का संचालन किया? **- पूर्वी लहर**
- 20 अप्रैल, 2024 को 'आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ' विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? **- डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में**
- भारतीय थल सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित 'मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल' हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण कहां किया? **- पोखरण फायरिंग रेंज में**
- 9 अप्रैल, 2024 को जम्मू-कश्मीर में आयोजित नवरेह उत्सव किसे समर्पित है? **- देवी शारिका**
- संगीत नाटक अकादमी द्वारा 9 से 17 अप्रैल, 2024 के मध्य कहाँ पर 'शक्ति - संगीत और नृत्य के महोत्सव' का आयोजन किया जा रहा है? **- 7 अलग-अलग शक्तिपीठों में**
- 10 अप्रैल, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दो दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ पर किया? **- नई दिल्ली**
- सफल पीजोइलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? **- कमांड हॉस्पिटल, पुणे**
- 12 अप्रैल, 2024 को नई दिल्ली में प्रो. रमन मित्तल और डॉ. सीमा सिंह की पुस्तक 'द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी: रीकनेक्टिंग द बॉन्ड' का विमोचन किसने किया? **- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़**
- समाचार प्रसारण के लिए किसे एक्सचेंज 4 मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवाड्र्स (ENBA) लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? **- टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक विनीत जैन**
- केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है? **-मनोज पांडा**

आर्थिकी

- केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान देश में निजी उपयोग और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक से कितने टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है? **- 17 करोड़ टन**
- किस कंपनी ने गुजरात के मुंद्रा में विश्व के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की? **- अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड**
- इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माता ओमेगा सेकी मोबिलिटी (OSM) ने किसके साथ साझेदारी कर ओएसएम स्ट्रीम सिटी क्यूक (OSM Stream City Qik) लांच किया है? **- एक्सपोनेंट एनर्जी**
- विद्युत मंत्रालय के अधीन किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को 'नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण' श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? **- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) लिमिटेड**
- 145.38 एमएमटी कार्गो प्रबंधन की रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त करने के साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में कौन-सी बंदरगाह अथॉरिटी शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है? **- पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (PPA)**
- बेंगलुरु को दक्षिण भारत के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से एयर इंडिया ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं? **- बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (BIAL)**

अंतरराष्ट्रीय

- हाल ही में 'विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण' का आयोजन कहां किया गया? **- नीदरलैंड के रॉटरडैम में**
- हाल ही में 'शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक' कहां आयोजित की गई? **- कजाकिस्तान के अस्ताना में**
- किस देश की फूड एजेंसी ने 'एथिलीन ऑक्साइड' की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है? **- सिंगापुर**
- 21 अप्रैल, 2024 को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है? **- कुवैत में**
- 19 अप्रैल, 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंपीं? **- फिलीपींस**
- भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को दो 'डोर्नियर-228 विमान' सौंपे हैं? **- गुयाना**